राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 18 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

समय वो स्कूल है जिसमें हम सीखते हैं, समय वो आग है जिसमे हम जलते हैं।
-डेलमोर स्वार्त्ज

पारदर्शिता जरूरी

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है कि मतदाता द्वारा वोट किसी भी पार्टी को दिया जाता है पर वोट जाता भाजपा को है। इसलिए चुनाव आयोग ने ठोस कदम उठाते हुए इन संदेहों को मिटाने का फैसला किया है। मतदान प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाने के लिए अब सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी जो अभी तक पचास फीसद महत्त्वपूर्ण मतदान केंद्रों में ही की जा रही थी। यानी अब हर पोलिंग बूथ पर कैमरों के निगरानी होगी और वोटिंग की हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी। वेबकास्टिंग किसी कार्यक्रम या प्रस्तुति का सीधा प्रसारण है। यह वेबकास्टिंग चुनाव प्राधिकरण के आंतरिक उपयोग के लिए होती है। सभी राज्यों के मुख्य

निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि इंटरनेट संपर्कता वाले सभी क्षेत्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी। जिन जगहों पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आदि की उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। आयोग पर लगातार आरोपों के बाद यह महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हालांकि आरोपों की जांच के दौरान ठोस सबूत नहीं पेश किए जा सकेबल्कि ये पूर्ण रूप से फर्जी साबित हुए। परंतु इन विवादों से आयोग की स्वायत्तता व निष्पक्षता पर संदेह की छींटें जरूरत पड़ीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती हैं। मोदी सरकार बार-बार इन आरोपों को बुनियादी ठहराते हुए कहती है कि इनसे चुनाव हारने की हताशा परिलक्षित करती है। कुछ दिन पहले लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अंग्रेजी के लेख में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिक्सिंग के आरोप लगाए गए थे। आयोग ने इसका जबाव भी दिया। मगर राहुल ने इस पर भी तंज किया था। बेशक, 2014 के बाद से विपक्ष भाजपा के मुकाबले निरंतर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। खासकर सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कड़ी मशक्कत के बावजूद अपेक्षित नतीजे पाने में बुरी तरह असफल हुई है। अन्य क्षेत्रीय दल भी निष्पक्ष स्वआकलन की बजाय आयोग पर छींटाकशी से बाज नहीं आते। हालांकि चुनाव आयोग भी इस दरम्यान अपने विवादों में रहा है। उसके लक्ष्य डुलमुलाए हैं और मतदाताओं में भ्रम बढ़े हैं। राजनीतिक दलों को तथ्यहीन आरोपों से बाज तो आना ही होगा परंतु आयोग को भी अपनी साख बरकरार रखने के प्रयास करने होंगे। बिहार चुनाव के दरम्यान आयोग की इस नई व्यवस्था के नतीजे स्पष्ट तौर पर सामने भी आ आएंगे।

नहीं सुधरेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान आतंकवाद के पोषण को लेकर दुनिया भर में बदनाम है। किभी भी आतंकी घटना का सिरा पाकिस्तान से जुड़ा मिलता है। भारत पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करता रहता है। आतंकवाद के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक और 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत सीधी कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान के ढीठपन में बदलाव आता नहीं दिखता। लेकिन लगता है कि अबकी बार पाकिस्तान फिर मुश्किल में फंसने जा रहा है। आतंकवाद के वित्त पोषण की वैश्विक निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सोमवार को जो कहा उससे पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक हलकों में झुरझुरी छूट रही होगी। एफएटीएफ ने साफ कहा कि पहलगाम आतंकी हमला पैसों की मदद के बिना संभव नहीं था।

एफएटीएफ पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने से खुद को नहीं रोक पाया। यह दुर्लभ बात है क्योंकि आम तौर पर वह ऐसा करता नहीं है। इसके अलावा वह विभिन्न देशों की भी जांच तेज करेगा ताकि देखा जा सके कि वे आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। एफएटीएफ ने एक बयान में कहा, आतंकवादी दुनिया भर में लोगों की जान लेते और भय पैदा करते हैं। 22 अप्रैल, 2025 का पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमला और हालिया अन्य हमले आतंकवादी समर्थकों के बीच धन के हस्तांतरण के बिना नहीं हो सकते। पिछले एक दशक में यह तीसरा मौका है जब उसने किसी आतंकवादी हमले की निंदा की है। इससे पहले एफएटीएफ ने 2015 और 2019 में आतंकवादी हमलों के गंभीर मामलों में निंदा जारी की थी। भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने और हथियारों की खरीद के लिए धन मुहैया कराने की बात को बार-बार उजागर किया है। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों के लिए उसे एफएटीएफ की 'संदिग्ध सूची' में डालने की मांग ने एक बार फिर तेजी पकड़ा है। एएफएटीएफ अपनी एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) की 25 अगस्त की बैठक और 20 अक्टूबर की पूर्ण बैठक के लिए भारत पाकिस्तान की हरकतों पर डोजियर बना रहा है। भारत को एफएटीएफ से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान को पहले भी तीन बार 2008, 2010 और 2018 में संदिग्ध सूची में रख कर बाद में छोड़ा जा चुका है। आईएमएफ अरबों डॉलर का पैकेज दे चुका है, और तुर्किए, चीन और अमेरिका उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं।

बहस/मुनीष भाटिया

शब्दों की मर्यादा जरूरी

18 जून को अंतरराष्ट्रीय घृणा फैलाने वाले भाषणों का मुकाबला करने का दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और मानवीय चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित करने का अवसर है। वर्तमान डिजिटल युग में, जब संवाद की गति अभूतपूर्व हो गई है, तब शब्दों की मर्यादा और अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।

इस दिन का उद्देश्य केवल भाषणों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि उन सामाजिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना है जो असहमति को शत्रुता, विचार को नफरत और रचनात्मकता को विकृति में बदल देती हैं। वायरल होने की होड़ में लोग संयम और नैतिकता को दरकिनार कर रहे हैं। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता और हिंसा को सामान्यीकृत किया जाने लगता है। फिल्में, वेब सीरीज, ऑनलाइन वीडियो और गानों में जिस प्रकार की सामग्री परोसी जा रही है, वह न केवल शालीनता की सीमाओं का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों और युवाओं के मानसिक व नैतिक विकास पर भी प्रभाव डाल रही है। आज बच्चों के हाथों में मोबाइल है, और इंटरनेट की दुनिया में वे ऐसे कंटेंट तक पहुंच रहे हैं जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट है। डर्टी वेब सीरीज, फूहड़ गाने, और यूट्यूब वीडियो में अश्लीलता और अभद्रता को सामान्य बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। सेंसरशिप की कमी के कारण यह सामग्री बच्चों के चरित्र और सोच को गहराई से प्रभावित कर रही है। राजनीतिक स्तर पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग चिंता का विषय बन चुका है। हाल ही में एक राज्य में एक वरिष्ठ नेता द्वारा दिए गए बयान ने दोनों समुदायों के बीच तनाव को भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप दंगे तक हुए। घृणा फैलाने वाले भाषण केवल कानून का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि वे समाज के भीतर छिपी हुई नफरत को हवा देते हैं। यदि हम समय रहते शब्दों की मर्यादा, संवाद की शालीनता और डिजिटल नैतिकता को पुनर्स्थापित नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां घृणा, अश्लीलता और असंवेदनशीलता के अंधेरे में खो जाएंगी।

नियंत्रित तापमान फायदेमंद

वातानुकूलन

शशि झा

गर्मी के दिनों में बिजली की घोर किल्लत झेल रही सरकार ने बिजली की बचत करने और बिजली बिल कम करने के लिए कमर कस ली है। कार्बन डायऑक्साइड में गिरावट आने से इससे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। सरकार की योजना अब एयरकंडीशनर (एसी) के तापमान सेट करने को लेकर नया नियम लागू करने की है। अब आप घरों में एसी का तापमान 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रख सकते। यह नियम सभी घरों, कार्यालयों, दूकानों, मॉल्स, होटल, रेस्तरां यहां तक कि गाड़ियों में लगे एसी पर भी लागू होगा। अक्सर देखा गया है कि गर्मियों में बहुतायत से एसी चलाने और उसका तापमान 16 डिग्री तक रखने के कारण बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। अभी बाजार में मौजूद ज्यादातर एसी को 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक निर्धारित किया जा सकता है लेकिन नया नियम लागू होने के बाद यह सीमा 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तय हो जाएगी।

सरकार की इस पहल की नीयत पर निश्चित रूप से संदेह नहीं किया जा सकता। पहली बार उठाए जा रहे इस कदम से तात्कालिक रूप से तो बिजली बिल में कमी के रूप में बचत होगी ही, दीर्घकालिक अवधि में भी यह कदम लोगों और देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस कदम का उद्देश्य पूरे देश में एसी के तापमान के उपयोग को एक जैसा बनाने का है यानी अगर कोई बहुत ठंडा या बहुत गर्म तापमान चाहता है तो अब संभव नहीं हो पाएगा।

दरअसल, बिजली बिल में कमी लाने और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिहाज से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (बीईई) ने वर्ष 2020 में भी स्टार लेवल वाले सभी एसी के लिए 24 डिग्री को डिफॉल्ट तापमान तय किया था। लेकिन अब सरकार इसे लेकर ज्यादा संजीदा है, और उसका इरादा अधिक सख्ती से और सभी सेक्टरों में तापमान की सेटिंग के नियम को लागू कराने का है। इस पहल को अभी एक प्रयोग के तौर पर आरंभ किया जा रहा है, और निश्चित रूप से आगे चल कर इसे पूरे देश में अनिवार्य किया जा सकता है। इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार जल्द ही सभी एसी विनिर्माताओं और कॉमर्शियल भवनों को इसी के अनुसार डिफॉल्ट तापमान तय करने के लिए एडवायजरी जारी कर देगी। आर्थिक रूप से देखें तो भी यह काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर देश के ज्यादातर उपभोक्ता इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो इसे बिजली के अरबों यूनिट की बचत हो सकती है।

आम धारणा है कि एसी का तापमान 18 डिग्री पर रखने से कमरा तेजी से ठंडा होगा। इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि यह धारणा गलत है। अगर कमरे के बाहर का तापमान 40 डिग्री है तो कमरे को 26 डिग्री के तापमान पर

पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, भले ही आपने एसी का तापमान 18 डिग्री तय कर रखा है, या 26 डिग्री तय कर रखा है। बेशक, 18 डिग्री पर कमरा बाद में अधिक ठंडा बना रहेगा। लेकिन कम तापमान के लिए आपको एक प्रकार की कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब आप कम तापमान निर्धारित करते हैं, तो एसी का कंप्रेशर अधिक समय तक काम करता है, जिसका अर्थ है बिजली की अधिक खपत।

दूसरी तरफ, अगर आप एसी का तापमान बढ़ा कर 24 डिग्री कर देते हैं, तो कंप्रेशर को कम समय के लिए काम करना पड़ेगा जिससे बिजली की कम खपत होगी। जैसे ही वांछित तापमान पहुंच जाता है, कंप्रेशर काम करना बंद कर देता है, और केवल एसी का पंखा ही काम करता है। कंप्रेशर दुबारा तभी काम करता है, जब थर्मोसेट को तापमान में वृद्धि होने का सिग्नल मिलता है। क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, 24 डिग्री का तापमान भी आरामदायक ही होता है। भले ही बाहर में ज्यादा उमस की स्थिति ही क्यों न हो और फिर 18 या 22 डिग्री के तापमान की तुलना में इसमें ऊर्जा की मात्रा भी कम खर्च होती है। एक अध्ययन के अनुसार, एसी के तापमान में प्रत्येक डिग्री की वृद्धि 3 से 5 प्रतिशत तक की बिजली की बचत कर सकती है। एक अनुमान के अनुसार, एसी के तापमान को अगर 18 डिग्री से बढ़ा कर 27 डिग्री कर दी जाए तो सालाना साढ़े 6 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है। इसी के साथ-साथ इस दरम्यान बड़ी मात्रा में ऊर्जा का भी संरक्षण हो सकता है। उल्लेखनीय है कि एसी में बिजली की बचत केवल निर्धारित तापमान के जरिए ही नहीं होती है, बल्कि यह बचत एसी की स्टार रेटिंग, बाहर के तापमान, एसी के उपयोग की समयावधि, कमरे के आकार, कमरे में लोगों की संख्या जैसे सारे कारकों पर निर्भर करती है।

एक और दिलचस्प बात यह भी है कि 20 डिग्री से 28 डिग्री के बीच एसी का तापमान रखने के स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी बहुत सारे हैं। आंकड़ों के अनुसार, भारत में एसी की संख्या लगभग 100 मिलियन है, और हर वर्ष लगभग 15 मिलियन एसी लगाए जा रहे हैं। अगर एसी के तापमान में एक डिग्री की भी बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो इससे एनर्जी के उपयोग में 6 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है, और हम प्रति वर्ष लाखों गीगावॉट बिजली की बचत कर सकते हैं। कुल मिला कर सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य तो निश्चित रूप से बिजली की खपत खासकर गर्मी के दिनों, जब बिजली की मांग अपने पीक पर पहुंच जाती है, में कमी लाना है, लेकिन इससे आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी कम नहीं हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि एसी को 20 से 28 डिग्री तक निर्धारित करने से गर्मी से संबंधित बीमारियों के जोखिम में कमी, नींद की बेहतर गुणवत्ता और आराम तथा उत्पादकता में वृद्धि भी शामिल हैं। खास बात यह है कि हवा की गुणवत्ता के बेहतर होने से कई प्रकार के एलर्जी और अस्थमा को बढ़ावा देने वाले तथा प्रदूषक तत्वों से भी मुक्ति मिल जाती है। एसी तापमान के बेहतर नियंत्रण से गर्मी की चरम स्थिति से उत्पन्न होने वाले हीट स्ट्रोक या थकावट में तो आराम मिलता है, साथ ही अवसाद में कमी, बेहतर मूड और एकाग्रता तथा कार्यशीलता में भी सुधार होता है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> दिलचस्प बात यह भी है कि 20 डिग्री से 28 डिग्री के बीच एसी का तापमान रखने के स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी बहुत सारे हैं। आंकड़ों के अनुसार, भारत में एसी की संख्या लगभग 100 मिलियन है, और हर वर्ष लगभग 15 मिलियन एसी लगाए जा रहे हैं। अगर एसी के तापमान में एक डिग्री की भी बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो इससे एनर्जी के उपयोग में 6 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है, और हम प्रति वर्ष लाखों गीगावॉट बिजली की बचत कर सकते हैं

- किशमिश न केवल शरीर में खून की कमी दूर करने में मदद करती है, बल्कि पोषक तत्वों का भी खजाना है
- हेल्थ एक्सपर्ट किशमिश को सुपर फूड बताते हैं। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट में प्रकाशित एक शोध लेख के अनुसार, किशमिश सूखे अंगूर हैं। हालांकि, इनमें चीनी ज्यादा होती है, फिर भी ये ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें हेल्दी स्नैक माना जाता है
- आयुर्वेद के अनुसार, किशमिश आयरन का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करती है। किशमिश में मौजूद कैल्शियम और बोरोन जैसे तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला है, ट्रंप परिवार-नियंत्रित कारोबार समूहों ने अपनी सौदेबाजी, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है, के जरिये अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित किया है। अब ट्रंप संगठन यूएस-बिल्ट स्मार्टफोन टी-1 की अगस्त महीने से बिक्री की योजना बना रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कि ट्रंप ने भारत या अन्य देशों में निर्मित आईफोन पर अतिरिक्त टैरिफ का निशाना क्यों साधा?

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक@Chellaney

मोदी सरकार के 11 वर्ष **मुकेश राजपूत**

आधुनिक भारत का स्वर्णिम काल

जून 9, 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने ग्यारह वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इन पिछले 11 सालों में दुनिया ने भारत की आर्थिक-सामरिक शक्ति को देखा है। लोगों के रहन-सहन में बदलाव आया है। आम नागरिक स्वच्छता के प्रति संवेदनशील हुआ है। इस साल के आरंभ में प्रयागराज में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ था। वहां छोटे से छोटा दुकानदार भी यूपीआई से पेमेंट ले रहा था। इनमें से कइयों के खातों में एक लाख से ऊपर बचत भी हो गई है।

मोदी सरकार की जन धन योजना और डिजिटल पेमेंट की क्रांति के कारण यह संभव हो पाया। अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के चंद महीनों बाद मोदी ने जन धन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 55 करोड़ से ऊपर खाते खुले जिनमें ग्रामीण और कस्बों में 36.63 करोड़ खाते हैं। इन खातों में 2.30 लाख करोड़ रुपये की धनराशि जमा है। अच्छी बात यह है कि इसमें 55.6 प्रतिशत यानी 29.37 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। यह भी सच है कि दिसम्बर 2023 में 20 प्रतिशत खाता निष्क्रिय थे। हालांकि निष्क्रिय खातों में भी 12779 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जब क्रांति आई तो सबसे बड़ा गेमचेंजर यूपीआई पेमेंट बना है।

इस विधि में पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है। यदि जन धन योजना में इतनी बडी संख्या में बैंक खाते न खोले गए होते तो शायद यूपीआई पेमेंट सफल नहीं हो पाता। आज छोटे से छोटा पेमेंट भी यूपीआई से संभव है और छोटे कारोबारी भी बचत करने लगे हैं, जिससे उनके रहन-सहन में भी सुधार हुआ है। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ही पहली बार स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना लेकर आई लेकिन ईमानदारी से किसी ने इस मिशन को पूरा किया तो वो है मोदी सरकार। 2 अक्टूबर, 2014 को मोदी ने गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। आज 9.63 करोड़ से अधिक शौचालय बना कर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। यह ऐसा कदम है जिससे महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। भारत के सिर से एक कलंक भी मिट गया।

वर्ष 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने तो सड़क निर्माण में

अभूतपूर्व क्रांति ही ला दी। आज कनेक्टिविटी के मामले में भारत विकसित देशों से पीछे नहीं है। देश में एक्सप्रेस-वे और हाई-वे का जाल बिछ गया है।

2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की विद्युत व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। भारत के शत प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हुआ। उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना, फीडर सेपरेशन से आज गांव जगमगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास मजबूत नवीकरणीय ऊर्जा इको सिस्टम बनाने का स्पष्ट दृष्टिकोण था। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक प्राथमिकता बनने से बहुत पहले बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं का बीड़ा उठाया था। 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने उस विजन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। प्रधानमंत्री के विजन के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना परिवर्तनकारी पहल है। पीएम कुसुम योजना किसानों को कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित कर रही है। हमें वे दिन भी याद हैं जब दो बोरी सीमेंट खरीदने के लिए तहसीलदार से परमिट लेना पड़ता था। चीनी भी कंट्रोल की दुकान से मिलती थी। एलपीजी और टेलीफोन कनेक्शन या तो किसी सांसद से मांगो अथवा दो-चार महीने इंतजार करो। अपनी किताब 'इंडिया अन्बॉन्ड्स' में गुरुचरणदास ने लिखा है कि किसी कंपनी को ज्यादा मंजन बनाने की आवश्यकता होती थी तो सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उद्योगपति भी परेशान थे। इंस्पेक्टर नीति के कारण भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तय सीमा से अधिक उत्पादन करने पर उद्योगपतियों की सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी।

पहले कोई महामारी फैलती थी तो हम आयातित वैक्सीन पर निर्भर रहते थे। परंतु कोविड-19 जैसी महामारी काल में भारत ने सबसे पहले स्वयं वैक्सीन बनाई और 100 से अधिक देशों को निर्यात भी की। आज भारत में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्स की संख्या बढ़ कर 23 हो गई है। आयुष्मान योजना से अंतर्गत 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए। सभी राज्यों में 11000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वैलनेस सेंटर खुलवाए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। 8 नये आईआईएम, 7 नये आईआईटी 490 नये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, विश्वस्तरीय काशी विश्वनाथ करिडोर, महाकाल परियोजना और अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम मंदिर अब सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। नारी शक्ति वंधन अधिनियम से लोक सभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला है। तीन तलाक जैसे कानून समाप्त किए गए हैं।

(लेखक उप्र के फर्रुखाबाद से सांसद हैं)

भय **श्रीराम शर्मा आचार्य**

भय में अपनी दुर्बलता की अनुभूति प्रथम कारण है, और दूसरा कारण है-हर स्थिति को अपने विपरीत मान बैठना। आशंकाग्रस्त व्यक्ति भोजन में विष मिला होने की कल्पना करके स्त्री द्वारा बनाने और परोसे जाने पर भी शंकाशील रहते हैं। ग्रह नक्षत्रों तक के प्रतिकूल होने, दूरस्थ होने पर भी विपत्ति खड़ी करने की कल्पना करते रहते हैं। जैसा का तैसा मिल भी जाता है। डरपोकों को और अधिक डराने वाली उक्तियां बताने और डर पैदा करने वाली घटनाएं सुनाने वाले भी कहीं न कहीं से आ टपकते हैं। अपने ऊपर भूत के आक्रमण की आशंका हो तो वैसी चर्चा करते ही ऐसे लोग तत्काल मिल जाएंगे जो उस भय का समर्थन करने वाले संस्मरण सुनाने लगेंगे। भले ही वे सर्वथा कपोल कल्पित ही क्यों न हों। हां में हां मिलाने की आदत आम लोगों की होती है। ऐसे में हालात ऐसे बन जाते हैं कि आम जन तो क्या ज्ञानी और चतुर-सुजान व्यक्ति को भी अंदाजा नहीं हो पाता है कि वस्तुस्थिति क्या रही होगी, या क्या है। वैसे भी आज के समय में आम भ्रान्तियों का खण्डन करके सही मार्गदर्शन कर सकने योग्य बुद्धिमानों और सत्याग्रहियों की बेतरह कमी हो गई है। उस पर गिरे को गिराने वाले 'शाह मदारों' की ही भरमार पाई जाती है। फलतः भ्रमग्रस्तों को और अधिक उलझन में फंसा देने वाले ही राह चलते मिल जाते हैं। भ्रान्तियों के बढ़ने का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहता है। और भ्रम का ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकल पाना भी आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं रहता। ताओ धर्म के प्रवर्तक लाओत्स ने एक दृष्टांत लिखा है-यमराज ने प्लेग को दस हजार व्यक्ति मार लाने के लिए हुक्म दिया। वह काम पूरा करके लौटे तो साथ में एक लाख मृतकों का समुदाय था। यमराज ने क्रुद्ध होकर इतनी अति का कारण पूछा। मौत ने दृढ़तापूर्वक कहा-'उसने दस हजार से एक भी अधिक नहीं मारा। शेष लोग तो डर के मारे खुद ही मर गए हैं।' मस्तिष्क को शान्त रखने में इच्छित परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अपने सोचने का तरीका बदल देने और तालमेल बिठाते हुए सौम्य और शान्त स्तर का जीवन यापन करने की कला सीखने और अभ्यास में उतारने भर से काम चल सकता है।

रीडर्स मेल

जंग तो खुद ही एक मसअला है

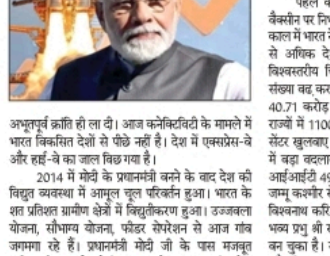

'जंग क्या मसअलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसअला है', शायर साहिर लुधियानवी की इन पंक्तियों में कितनी गहरी और बड़ी बात छिपी हुई है। दुनिया में हर तरफ हिंसा और अशांति का माहौल है। रूस-यूक्रेन युद्ध 3 वर्षों से जारी है, इस्राइल-हमास का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब इस्राइल-ईरान में भी युद्ध शुरू हो गया है। पता नहीं दुनिया अब किस माहौल में जीने की आदी हो गई है; कोई व्यक्ति, देश, परिवार हो हर स्तर पर आपसी द्वंद्व छिड़े हुए हैं। आए दिन हर देश अब परीक्षण करते रहते हैं। देशों की आपसी अनर्गल बयानबाजी, युद्ध की धमकी, परमाणु परीक्षण, युद्धाभ्यास अब जैसे आम बात हो गई है। रूस-यूक्रेन युद्ध से आर्थिक मोर्चे पर भी पूरी दुनिया में असर दिखाई दिया है। अब इस्राइल-ईरान के संघर्ष से यह असर और व्यापक होगा। आज हर देश को समझने की आवश्यकता है कि यह समय युद्ध का नहीं, बल्कि मिलजुलकर विकास के पथ पर बढ़ने का। है। यह समय संयम और सावधानी बरतने का भी है क्योंकि व्यापक और उन्नत हथियारों के इस युग में पूरी पृथ्वी बारूद का ढेर बनी हुई है, जिस पर उठी एक चिंगारी भी सब कुछ राख कर सकती है।

नितिन रावत, फिरोजाबाद, उप्र

चोकर का टैग हटाया

दक्षिण अफ्रीका की टीम को 27 साल का लंबा अंतराल लगा इस आईसीसी ट्रॉफी को जीतने के लिए। आखिरकार, उनके नाम के साथ जुड़ा चोकर का टैग भी अब हट गया है। उनकी डब्ल्यूटीसी की जीत की महत्ता और बढ़ जाती है जब हम यह जानते हैं कि उन्होंने यह सफलता उस ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ हासिल की है जिसने अब तक 13 आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल खेले हैं, और 10 में जीत हासिल की है। और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 82 रनों की बढ़त भी दे दी थी लेकिन उसके बाद रबाडा की धारदार गेंदबाजी और मारक्रम के शानदार शतक और बावुमा की धैर्य वाली पारी ने दक्षिण अफ्रीका को जीत का स्वाद चखवाया। यह जीत न केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि विश्व क्रिकेट विशेषकर टेस्ट क्रिकेट के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। आशा है कि दक्षिण अफ्रीका में बच्चे भी इस जीत से प्रेरणा लेंगे।

बाल गोविंद, ई मेल से

पर्यटन विरोधी प्रदर्शन चिंताजनक

पर्यटन अनंतकाल से दुनिया भर के देशों के लिए आर्थिक स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। स्पेन, इटली और पुर्तगाल जैसे कुछ यूरोपीय देशों में अत्यधिक पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण पर्यटन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इन लोकप्रिय स्थलों के निवासी बढ़ती आवास लागत, स्थानीय संसाधनों पर दबाव और पर्यटकों की आमद से जीवन की समग्र गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता जता रहे हैं, खासकर पीक सीजन के दौरान। सामूहिक पर्यटन पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। क्या यह विरोध आहिस्ता आहिस्ता पूरे विश्व में भी फैल सकता है? उत्तर है 'हां' ऐसा हो सकता है। 2023 में वैश्विक पर्यटन क्षेत्र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 33 करोड़ नौकरियों का सृजन करने में सफल रहा था। क्या अब उसमें गिरावट आनी शुरू होगी?

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 300
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। | स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* |
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान 1936

संघर्ष अभी बेलगाम

ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष जैसे-जैसे बढ़ रहा है, चिंता भी बढ़ती जा रही है। ईरान और खासकर उसकी राजधानी तेहरान में ऐसे लोग हैं, जिन्हें शुक्रवार से ही चैन की नींद नसीब नहीं हुई है। लोग भाग रहे हैं। अमेरिका ने यह बोलकर तनाव को बहुत बढ़ा दिया है कि ईरानी लोग तेहरान खाली कर दें। ऐसे में, भारत सरकार भी तेहरान से भारतीयों को हटाने में लगी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अमेरिकी रुख से ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इजरायल को यह मंजूरी दे दी है कि वह तेहरान में खुलकर हमले करे। वैसे, तो ईरान भी कम नहीं है और वह इजरायल की राजधानी तक घुसकर वार कर रहा है। ईरानी रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने मंगलवार को बताया है कि उसे इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के केंद्र पर हमला करने में कामयाबी मिली है। ड्रोन और मिसाइल के जरिये ईरान भी इजरायल को निशाना बना रहा है, जिससे इजरायल की आक्रामकता बढ़ती जा रही है।

कुल मिलाकर, दोनों देश संघर्ष बढ़ाने में लगे हैं। एक उम्मीद जी-7 के देशों से थी, पर वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। जी-7 देशों के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शत्रुता को कम करने का आग्रह तो किया है, मगर इजरायल-ईरान संघर्ष को छोड़ दिया गया है। दुनिया के ताकतवर देश अपने शिखर सम्मेलन के दौरान इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम का आह्वान करने से चूक गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिखे और आनन-फानन में कनाडा से अपने देश लौट गए। लौटने का एक बड़ा कारण इजरायल-ईरान संघर्ष बताया जा रहा है। उन्होंने इस संघर्ष पर कोई भी आश्वासन नहीं दिया है और न किसी बड़े प्रयास के संकेत दिए हैं। अतः जिन लोगों को यह उम्मीद होगी कि कनाडा में संघर्ष विराम की कोशिशें होंगी, उन्हें बहुत निराशा होगी। अमेरिका इस संघर्ष को बहुत गंभीरता से ले रहा है और उसके रुख से ऐसा लगता है कि वह इजरायल को हमले की रियायत देना जारी रखेगा। भूलना नहीं चाहिए कि ईरान समय-समय पर अमेरिका के विरोध में भी बोलता रहा है। ऐसे में, अमेरिका शायद यही चाहेगा कि ईरान सामरिक-आर्थिक स्तर पर कमजोर हो जाए। इजरायल को संघर्ष में कुछ नुकसान तो हो रहा है, पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा कामयाबी मिलती दिख रही है।

जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन से बहुत उम्मीदें थीं, पर वहां इजरायल-ईरान संघर्ष विराम पर कोई खास बात नहीं हुई है। बेशक, यह भारत के लिए सजगता का समय है।

ईरान के सर्वोच्च नेता 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई अपने देश में ही कमजोर और बेबस होते नजर आ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान मानीखेज है कि अली खामेनेई को खत्म करने से युद्ध नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह खत्म हो जाएगा। इजरायल के इस इरादे के पीछे अमेरिका है, ये दोनों देश चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने में सक्षम न हो सके। जब यह लग रहा है कि संघर्ष जल्दी खत्म नहीं होगा, तब तेहरान के आम लोगों की चिंता सबको होनी चाहिए। भारत जैसे देश को बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि ईरान के साथ भारत के हित जुड़े हैं। भारत अपने 80 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल के आयात के लिए फारस की खाड़ी पर निर्भर है, यह तेल जिस मार्ग से आता है, वह भी ईरान के तहत आता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ा, तो यहां नाकाबंदी होगी और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी। भारत को सतर्क रहना होगा और सरकार ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तेल के अन्य स्रोतों को खंगाला जा रहा है। भारत को ईरान में मौजूद भारतीयों और भारतीय हित के साथ ही, अपनी तेल-आपूर्ति का भी पूरा ध्यान रखना होगा।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 18 जून, 1950

मंत्रियों की व्यस्तता

भारत के स्वतंत्र होने के बाद प्रथम बार मंत्रिमंडल की बैठक राजधानी के बाहर हुई है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य तथा अस्वाभाविकता की बात नहीं, क्योंकि पं. जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं और उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। उप-प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं और वह देहरादून में हैं। अतः केवल मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता के लिए उनका दिल्ली आना उन पर अनावश्यक भार डालता।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य इस समय राजधानी से बाहर हैं। लेकिन ये सैर-सपाटे के लिए दिल्ली से बाहर नहीं गये हैं। उनकी यात्रा का विशेष उद्देश्य है। नेहरूजी की दक्षिण-पूर्वी एशिया की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसके सम्बन्ध में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं। भारत की स्वास्थ्य-मंत्रिणी राजकुमारी अमृतकौर विश्व स्वास्थ्य-संगठन के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के बाद काहिरा पहुंच गई हैं और वहां भी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य-केन्द्रों का निरीक्षण कर 19 जून तक दिल्ली वापस आ जाएंगी। इसी प्रकार भारत के श्रम-मंत्री श्री जगजीवन राम ने भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इन दो बड़े अन्तर्राष्ट्रीय पदों पर भारतीय प्रतिनिधियों का निर्वाचन भारत के लिए गौरव तथा सम्मान की बात है। यह इस तथ्य का सूचक भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एशिया का महत्व बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री के पद के लिए श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लिया जा रहा है। वास्तव में, इस पद के लिए यह सर्वथा उपयुक्त हैं। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की इंडोनेशिया-यात्रा सोलहों आने सफल सिद्ध हुई है। बाली तथा इंडोनेशिया के दूसरे स्थानों में नेहरूजी का जैसा स्वतःस्फूर्त तथा उल्लासपूर्ण स्वागत हुआ, वह इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णांकित रहेगा। बाली के सुरम्य प्राकृतिक स्थलों, नृत्यों तथा प्राचीन बौद्ध मूर्तियों व मन्दिरों को देखने के बाद भारत तथा इंडोनेशिया के बीच की ऐतिहासिक शृंखला और भी सुस्पष्ट रूप में नेहरूजी के सामने उपस्थित हो गई होगी। इंडोनेशिया की इस यात्रा का क्या उद्देश्य था, इसके सम्बन्ध में भी नेहरूजी अपने भाषणों तथा पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रकाश डाल चुके हैं।

मध्य एशिया से आंख न मूंदे भारत

श्रीनाथ श्रीधरन | कॉरपोरेट सलाहकार

भारत का अधिकांश तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है। इस मार्ग को खतरे में डालने वाली किसी भी गतिविधि से तेल की कीमत, आपूर्ति सुरक्षा व घरेलू मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ेगा।

ईरान (फारस) के प्राचीन शहर पर्सेपोलिस का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। लंबे समय तक कूटनीति, व्यापार और रणनीतिक शह-मात तले दफ्न फारसी साम्राज्य की पुरानी स्मृतियां एक बार फिर जंग की शक्ल में जिंदा हो उठी हैं। पिछले सप्ताह से ही इजरायल और ईरान द्वारा एक-दूसरे पर मिसाइलों की बरसात की जा रही है और इस टकराव ने शांति का नोबेल पाने की आस लगाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन (14 जून) के जलसे को फीका कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध में बीच-बचाव में लगे हुए हैं।

हालांकि, वाशिंगटन ने इजरायली हमलों को औपचारिक रूप से अपनी हरी झंडी नहीं दिखाई है, मगर तेहरान का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका की मौन सहमति से ही इजरायल ने यह हिमाकत की है। घटनाएं इसी संदेह की पुष्टि करती हैं, क्योंकि ट्रंप ने तुरंत इजरायल की कार्रवाई को 'उत्कृष्ट' बताते हुए उसकी प्रशंसा की थी। अब पूरे क्षेत्र में प्रतिशोध की जो आग भड़क रही है, उससे न केवल पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, बल्कि यह एक ऐसी भू-राजनीतिक ज्वाला बन चुकी है, जिसकी जद में पेट्रोलियम आधारित तमाम अर्थव्यवस्थाएं, समुद्री मार्ग और कूटनीतिक प्रयास आने लगे हैं।

इजरायल का रुख बिल्कुल साफ है। यद्यपि आधिकारिक रूप से वह यही कहता रहा है कि उसका इरादा ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करना है, लेकिन वास्तव में उसकी महत्वाकांक्षा बहुत गहरी है। इजरायल का ईरान के लोगों से यह आह्वान करना कि वे अपनी प्राचीन पहचान को फिर से हासिल करने के लिए अपने दमनकर्ता इस्लामी निजाम के खिलाफ खड़े हों, यही संकेत देता है कि यह परमाणु खतरा रोकने से कहीं अधिक व्यापक इरादे वाला अभियान है। यह ईरान में सत्ता-परिवर्तन का गहरा प्रयास है। लेकिन इतिहास हमें यही बताता है कि ऐसी कोशिशें शायद ही कभी कामयाब हुई हैं। आर्थिक नुकसान और आंतरिक दबाव झेलने के बावजूद ईरान आज भी सुरक्षा के लिहाज से मजबूत, वैचारिक रूप से दृढ़ और क्षेत्रीय रूप से अच्छे नेटवर्क वाला मुल्क है।

निस्संदेह, 1980 के दशक में इराक के साथ आठ साल तक भीषण युद्ध लड़ने के बाद ईरान पहली बार इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पर वह पीछे नहीं हटेगा, बल्कि यह दोगुने उत्साह से राष्ट्रवाद का आह्वान कर सकता है, युद्ध को और तेज कर सकता है और अपने पश्चिम विरोधी रुख को अधिक कठोर कर सकता है। इसका कूटनीतिक धैर्य पहले ही जवाब दे चुका है। अमेरिका के साथ उसकी परमाणु वार्ता बंद हो चुकी है। तेहरान समर्थित आतंकी गुट कमजोर पड़े हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुए हैं। ये फिर से मैदान में आ सकते हैं।

ईरान और इजरायल कभी मित्र भले न रहे हों, पर उनके बीच एक वक्त गोपनीय सहयोग का रिश्ता था। शाह के शासनकाल में इन दोनों के बीच खुफिया तालमेल, रक्षा सामग्रियों का लेन-देन और व्यापार बहुत गहरा था। इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद अरब देशों के मुंह मोड़ लेने के बाद ईरान इजरायल से जुड़ गया था। लेकिन दोनों के बीच का यह अल्पकालिक गठजोड़ 1979 की ईरान में इस्लामिक क्रांति के साथ ही समाप्त हो गया। इसके बाद दशकों से कायम आपसी संदेह, छद्म संघर्ष अब आमने-सामने की जंग में बदल गया है। यह युद्ध दो ऐसे पहलवानों के बीच है, जो एक-दूसरे की ताकत और कमजोरियों को बखूबी जानते हैं।

इस बीच, कनाडा में चल रहे जी7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन और व्यापार युद्धों पर ध्यान केंद्रित किया जाना था, मगर अब पश्चिम एशिया का युद्ध उसके एजेंडे पर हावी हो गया है। अमेरिका के साथी देश, जो पहले ही युद्ध की थकान और मुद्रास्फीति के दबाव से परेशान हैं, एक और अस्थिरता फैलाने वाला बड़ा संकट झेलने को तैयार नहीं हैं। आखिर इनमें से हरेक नेता को अपना घरेलू चुनाव भी जीतना है। ईरान-इजरायल युद्ध का तेल बाजार में त्वरित प्रतिक्रिया हुई। कच्चे तेल की कीमत में करीब 10 प्रतिशत की तेजी आई, और यह 80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। इसके अलावा (होर्मुज) जलडमरूमध्य की नाकाबंदी का खतरा उत्पन्न हो गया है। यह युद्ध दुनिया में तेल आपूर्ति की राह में बाधा डाल सकता है। दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से आता-जाता है। यदि यह मार्ग बाधित हुआ, तो वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा।

ऐसे में, भारत को अब अस्थिर पड़ोस के साथ जीने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। उसे पूरी स्पष्टता के साथ इस समय को पढ़ना चाहिए। इजरायल और ईरान, दोनों के साथ हमारे रणनीतिक संबंध हैं। ईरान से साझेदारी की हमारी जड़ें तेल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे और भौगोलिकता में हैं। मध्य एशिया से जुड़ने का भारत का महत्वपूर्ण प्रवेश-द्वार चाबहार बंदरगाह युद्धक्षेत्र के करीब ही है। ईरान संकट में आया, तो हमारी पश्चिमी आकांक्षाओं की राह में रुकावट आ सकती है। इजरायल से रक्षा, प्रौद्योगिकी व नवाचार के क्षेत्र में हमारा गहरा रिश्ता है। यह सैन्य व साइबर-रक्षा प्रणालियों के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है।

इजरायल-ईरान टकराव कोई ऐसा संघर्ष नहीं है, जिससे भारत लंबे समय तक अपनी आंखें मूंद सके। भारत ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन द्वारा इजरायली हमले की निंदा वाले बयान से खुद को अलग रखने का फैसला किया। निस्संदेह, यह उसके स्वतंत्र रुख और किसी गुटबाजी से इनकार का एक सुचिंतित संकेत है। मगर गुटनिरपेक्षता का मतलब चुप्पी नहीं होता। भारत को कूटनीतिक दांव-पेच से आगे का सोचना होगा और उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। भारत का अधिकांश तेल जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इस मार्ग को खतरे में डालने वाली किसी भी गतिविधि से तेल की कीमतों, आपूर्ति सुरक्षा और घरेलू मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ जाएगा। तेल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, रुपये पर दबाव बढ़ेगा और हमारा मुद्रा भंडार कम होता जाएगा।

भारत को पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तेल भंडारण के अलावा खाड़ी के तेल आपूर्तिकर्ता साझेदार देशों से गंभीर द्विपक्षीय आश्वासन पर बात होनी चाहिए। नई दिल्ली के पास अपूर्व कूटनीतिक पूंजी है। वह तेल अवीव और तेहरान, वाशिंगटन और रियाद, मास्को और ब्रुसेल्स से बेहिचक बात कर सकती है। अपनी इस कूटनीतिक क्षमता का उपयोग हमें वैश्विक कूटनीति, रणनीतिक जुड़ाव और दुनिया को दृढ़ संदेश देने के लिए करना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हमारी खगोलीय तरक्की के शानदार ग्यारह साल

डॉ जितेंद्र सिंह | केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

केरल के थुंबा में मछली पकड़ने वाले एक शांत गांव के चर्चयार्ड से साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक दिन देश इन ऊंचाइयों को छू लेगा। वह समय दृढ़ संकल्प का था, जब सितारों तक पहुंचने का सपना सीमित साधनों, पर असीम महत्वाकांक्षा के साथ परवान चढ़ा।

वह सपना विकसित होकर अब एक राष्ट्रीय मिशन का रूप अख्तियार कर चुका है और आज जब हम नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष के सफर पर गौर कर रहे हैं, तब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में आमूल-चूल बदलाव आ चुका है। यह परिवर्तन केवल रॉकेट और उपग्रहों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन के बारे में है। यह दर्शाता है कि दूरदराज के गांव के किसान से लेकर डिजिटल कक्षा के छात्र तक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी में खामोशी से शामिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के रणनीतिक नेतृत्व में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की नए सिरे से परिकल्पना की है। साल 2014 से शुरू किए गए सुधारों ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। 2020 में इन-स्पेस की स्थापना ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे नवाचार की लहर उठी। आज 300 से भी अधिक अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप उपग्रह बना रहे हैं, प्रक्षेपण वाहन डिजाइन कर रहे हैं तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नेविगेशन के क्षेत्र में सेवाएं देने वाले अनुप्रयोग विकसित कर रहे हैं। ये स्टार्टअप प्रौद्योगिकी ही नहीं सृजित कर रहे, खासकर टियर-2 व टियर-3 शहरों में युवा इंजीनियरों और उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसरों का भी सृजन कर रहे हैं। उदारीकृत अंतरिक्ष नीति ने अंतरिक्ष सेवाओं को अधिक किफायती व सुलभ बना दिया है, जिससे उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है।

साल 2014 से उठाए गए कदमों की बदौलत आज 300 से अधिक अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप उपग्रह बना रहे हैं, प्रक्षेपण वाहन डिजाइन कर रहे हैं।

भारतीय उपग्रह मौसम पूर्वानुमान में अहम भूमिका निभाते हैं, जिनकी बदौलत किसानों को अपनी बुवाई व कटाई-चक्र की योजना सटीकता से बनाने में मदद मिल रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उपग्रह डाटा प्रारंभिक चेतावनी और आपदा प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है, जिससे जीवन व आजीविका की रक्षा होती है। इसी तरह, सैटेलाइट बैंडविड्थ समर्थित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म दूरदराज के गांवों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

बीते दशक में शुरू किए गए मिशनों ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। मंगलयान हमारी इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता पर मुहर लगाते हुए अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा और इसके रोवर ने ऐसे प्रयोग किए, जो भविष्य के चंद्र मिशनों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। आदित्य-एल1 अब सौर तूफानों का अध्ययन कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मौसम तथा संचार प्रणालियों व बिजली ग्रिड पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिल रही है। भविष्य पर गौर करते हुए भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। इसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है और अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग की हाल की सफलता ने इस बड़े लक्ष्य के लिए आवश्यक तकनीक की पुष्टि की है। इस लिहाज से भारत अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) का विकास कर रहा है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 30,000 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है।

अगले दशक पर गौर करें, तो हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं : साल 2040 तक चालक दल के साथ चंद्रमा पर उतरना, पूरी तरह से चालू अंतरिक्ष स्टेशन, और वैश्विक अंतरिक्ष नवाचार में नेतृत्व की भूमिका। ये केवल सपने नहीं हैं, ये एक ऐसे राष्ट्र की रणनीतिक अनिवार्यताएं हैं, जिसने हमेशा समाज को बदलने के लिए विज्ञान की शक्ति में विश्वास किया है। थुंबा के साइकिल शेड से लेकर कक्षा में डॉकिंग मैन्युवर तक, भारत की अंतरिक्ष यात्रा दृढ़ता, कल्पनाशीलता और अथक प्रयास की दास्तान है। और अब, जब हम परिवर्तनकारी शासन के ग्यारह वर्षों का जश्न मना रहे हैं, तब हम एक ऐसे राष्ट्र का भी कीर्तिगान कर रहे हैं, जो वास्तव में सितारों तक जा पहुंचा है और उनकी रोशनी को वापस घर ले आया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आध्यात्मिक होने के लाभ

आपके मन में उठता होगा कि आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने से क्या लाभ होगा और वहां तक जाने का रास्ता क्या है?

दरअसल, मानव का मानसिक बल असीम है, पर अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका समय क्षुद्र विचारों में व्यतीत हो जाता है। इस मानसिक अपव्यय को नियंत्रित करने के तीन मार्ग हैं- शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण पाना चाहिए, क्योंकि श्वास की गति का सीधा संबंध विचारों की गति से है। जब मन स्थूल विषयों में उलझा हो, तब श्वास तेज हो जाती है; लेकिन जब यह सूक्ष्म विचारों में लीन हो, तो सांसों की गति मंद हो जाती है। जब श्वास और विचार एक लय में आ जाएं, तो उसे हठयोग समाधि कहा जाता है। इसलिए साधक को अपनी सांसों पर अवश्य नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा मार्ग है- तर्कशीलता व विवेक को बढ़ाना। इसके लिए मन और शरीर से अनावश्यक तरंगों को हटाना होगा। साधक को यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि उसे तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना है। जब अनावश्यक विचार हटा दिए जाते हैं, तब मन तर्कशील चिंतन में संलग्न होता है।

चिंतन और ध्यान, दोनों मानसिक प्रवाह से जुड़े हुए हैं। चिंतन के लिए शरीर की ग्रंथियों और उप-ग्रंथियों का संतुलन आवश्यक है। केवल भावना पर्याप्त नहीं, चिंतन के लिए स्पष्ट विचार का आधार भी जरूरी है। व्यक्ति को किसी गूढ़ शक्ति की याचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि परम पुरुष की भावना लेकर उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंतन जब आनंद से युक्त होगा, तभी वह साधक को ध्यान के उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है।

ध्यान एक पद्धतिपूर्वक किया गया मानसिक अभ्यास है, जिसमें मस्तिष्क के अनेक केंद्र सक्रिय होते हैं। ध्यान की सर्वोच्च अवस्था ही आध्यात्मिकता का चरम बिंदु है, जिसे प्राप्त करने के लिए मानव युगों-युगों से प्रयास करता आया है। यही प्रयास मानव को निरंतर आगे ले जाता है। जब मन विधिपूर्वक किसी अनुशासन या मार्ग का पालन करता है, तो उसको भक्ति कहते हैं, पर जब वह बिना किसी नियम के, मनमाने ढंग से चलता है, तो उसे भावना कहते हैं। भक्ति में अनुशासन व लक्ष्य की स्पष्टता होती है, जबकि भावना में असंतुलित आवेग होते हैं।

जब मनुष्य आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। यह बदलाव उसकी चेतना के केंद्र में घटित होता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है।

इस प्रकार ध्यान, चिंतन और भक्ति, तीनों का संतुलन जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी आचरण या सोच के स्तर पर नहीं होता, बल्कि उसकी चेतना के केंद्र में घटित होता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर और शांत हो जाता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

भारतीय ज्ञान परंपरा की विरासत बहुत पुरानी है। इसे केवल पूजा पद्धति और अभिमान के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य के हिसाब से हमें इसका विश्लेषण करना होगा।

अनुलोम-विलोम
जनगणना

इस जनगणना से प्रगति के द्वार खुलेंगे

देश में जनगणना कराने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। 16 जून को जारी अधिसूचना में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। इससे प्रगति की दिशा में काम करने में सुविधा होगी। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जनगणना टल रही थी, लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि आबादी की गिनती का काम जल्द शुरू हो जाएगा। देश में दो चरणों में जनगणना होगी। कोरोना महामारी की विभीषिका के कारण तय समय पर जनगणना टल गई थी और अब 2025 में इसकी शुरुआत होने जा रही है।

इस बार जनगणना की प्रक्रिया दो चरण में होगी, जिसका पहला चरण 01 अक्तूबर, 2026 तक पूरा किया जाएगा। जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च, 2027 तक पूरा होगा। इसी तारीख को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा, वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और फिर ये आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, जिसे आप भी जान सकेंगे। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्तूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इन राज्यों के लिए 1 अक्तूबर, 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का सिलसिलेवार परिसीमन 2028 तक होगा। इस दौरान महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण भी लागू किया जा सकता है। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ हो सकती है। इस बार की जनगणना में जाति और संप्रदाय से जुड़े सवाल भी शामिल किए जा सकते हैं। डिजिटल गणना के लिए सॉफ्टवेयर में जाति, उप-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे।

जनगणना में इस बार नए तरीके से कराने की योजना है। पहली बार जनगणना डिजिटल मोड में होगी। यानी, कागज-कलम की जरूरत खत्म। अब टैब और लैपटॉप में ही सारे कॉलम होंगे, जिन्हें जनगणना कर्मी खुद भरेंगे। इस तरह देश की ताजा सामाजिक, आर्थिक स्थिति का पता सटीक तरीके से चल पाएगा। इससे सामाजिक विषमता की खाई भरने के लिए योजनाएं बनाने में सरकारों को सुविधा हुआ करेगी। इस तरह हमलोगों को इस जनगणना का स्वागत करना ही चाहिए।

यूसुफ अली, टिप्पणीकार

देरी और कमियों को दूर करना जरूरी

देश में नई जनगणना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब अगले दो वर्षों में पूरे देश में लोगों की गिनती कर ली जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई खामियां और कमियां हैं, जो हमारे समाज को गर्त में धकेल सकती हैं। इस बार की जनगणना में जाति के आधार पर लोगों को गिना जाएगा। देश में पहले से ही जातिवाद हावी है। ऐसे में जातियों की संख्या की गिनती सार्वजनिक करके जातिवादी समूहों को और मजबूत बनाने का काम इस जनगणना से होगा। वैसे तो सभी धर्मों में अलग-अलग जातियों की गिनती की जाएगी, लेकिन इसमें सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय का होने वाला है। हिंदू धार्मिक समुदाय में न केवल वर्ण व्यवस्था है, बल्कि यहां अस्पृश्यता का दानव भी मौजूद है। अब तक अलग-अलग जातियों की संख्या पता नहीं होने के कारण जाति के आधार पर देश को बांटने वाले समूहों के पास कोई चारा नहीं होता था और थक-हारकर राष्ट्रीय चरित्र के अनुरूप ही राजनीति करने पर विवश हो जाते थे। लेकिन अब उन्हें जातियों की संख्या का ठीक-ठीक आंकड़ा पता चल जाएगा। सारा देश जाति की संकीर्ण राजनीति में ही उलझकर रह जाएगा। दिखावे के तौर पर सब यही कह रहे हैं कि जातियों की संख्या पता होने से उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होंगी। लेकिन यह एक थोथी दलील है, क्योंकि कल्याण की योजनाएं बनाने के लिए सरकारों को किसने अब तक रोका है? क्या आज जो देश की आबादी है, उसके आधार पर योजनाएं नहीं बनाई जा सकती हैं? ऐसा हो सकता है। मगर जाति गणना का असल मकसद कुछ और ही खेल करना है, जिसमें जातिवादी शक्तियां सफल हो गई लगती हैं।

इसके अलावा, इस बार की जनगणना मे काफी देर भी हुई है। पिछले लगभग 150 साल से जो जनगणना अपने समय पर चलती आ रही थी, चाहे वह विश्व युद्ध हो या अन्य कोई संकट, कभी रुकी नहीं। वह इस बार कोरोना महामारी के नाम पर 2021 में नहीं कराई गई। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि 2022 में इसे अलग तरीके से कराया जा सकता था। अब तो चार साल की देरी से अधिसूचना जारी हुई है और गणना होते-होते 2027 आ जाएगा। इस तरह सात साल की देरी हो जाएगी। संशय इस बात को लेकर भी है कि क्या अगली जनगणना समय से हो सकेगी? कहा तो जा रहा है कि अगली बार 2035 में जनगणना होगी। लेकिन इसे तो 2031 में ही होना चाहिए। इसमें संशय इस बात पर है कि सरकार 2035 का समय भी टाल दे और अगली बार सीधे 2041 में जनगणना कराए। सरकार को इसके बारे में स्पष्ट बताना चाहिए।

सुज्ञान चंद, टिप्पणीकार

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 18 जून 2025

युद्ध नहीं, शांति

इस्राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के पूर्ण युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब यह आशंका भी बढ़ गई है कि अमेरिका इस संघर्ष में सीधे शामिल हो सकता है। इससे हालात और जटिल हो जाएंगे, संभव है कि अनियंत्रित हो जाएं।

अस्थिरता बढ़ेगी । वक्त के साथ दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ता जा रहा है। इस्राइल ने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को लगभग खत्म कर दिया है और उसका ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की बात कहना मामले को और भड़काने वाला है। इससे अस्थिरता ही बढ़ेगी।

खत्म हो इस्राइल-ईरान जंग

अमेरिकी रुख । इस मामले में बहुत कुछ अब अमेरिकी रुख पर निर्भर करता है। डॉनल्ड ट्रंप ने इस वादे के साथ बतौर राष्ट्रपति अपनी दूसरी पारी शुरू की थी कि वह रूस-यूक्रेन और इस्राइल-हमास युद्ध को रुकवा देंगे। उन्होंने प्रयास भी किए, जो अभी तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन, ईरान के केस में उनका रवैया दूसरा दिखता है। वह G7 के महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले ही लौट गए और कहा कि मकसद कुछ बड़ा है।

पुराने सबक । अमेरिका और इस्राइल का स्पष्ट मत है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या इस मकसद के लिए पूर्ण युद्ध की ओर जाया जा सकता है और उसका असर क्या होगा? यूक्रेन में रूस के दाखिल होने से जो लड़ाई छिड़ी, उसका हल तीन साल बाद भी नहीं निकल सका है। इसी तरह, इस्राइल-हमास युद्ध शुरू हुए भी करीब 21 महीने होने को हैं।

आग फैल जाएगी । इन दोनों लड़ाइयों ने घोर मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, गाजा में भुखमरी के हालात बन गए और इस दौरान ऐसे कई मौके आए, जब लगा कि दूसरे देश भी इस टकराव में शामिल हो सकते हैं। वही जोखिम दोबारा नहीं लिया जा सकता। ईरान की स्थिति हमास या यूक्रेन से अलग है और उसके सीधे तौर पर जंग में उतरने का मतलब पूरे पश्चिम एशिया को आग में धकेलना हो सकता है।

आर्थिक संकट । इस लड़ाई का वैश्विक असर बहुत गहरा पड़ेगा और उसके संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दाम में एक ही दिन में पिछले तीन साल की सबसे बड़ी तेजी आई। डर है कि लड़ाई की वजह से होरमुज जलडमरूमध्य का वह समुद्री रास्ता ब्लॉक न हो जाए, जिससे होकर ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% जाता है। ईरान खुद भी बड़ा तेल उत्पादक देश है। भारत के लिए क्रूड ऑयल की महंगाई आर्थिक दुश्वारियां पैदा कर सकती हैं, जो इसके लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

नज़रिया

उड़ान पर अंकुश

डॉ. बृजेश सती

केदारनाथ धाम के लिए 2004 में पहली बार फाटा से प्रयोग के तौर पर हेली सेवा शुरू की गई थी। रेस्पॉन्स इतना अच्छा रहा कि इसे नियमित कर दिया गया। 2005 में पवन हंस ने अगस्त्यमुनि मैदान से केदारनाथ के लिए उड़ान शुरू की। देखते ही देखते केदारनाथ धाम के लिए फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी से भी हेली सेवा चलने लगी। फिलहाल चार धाम में 9 कंपनियां हेली सेवा दे रही हैं। इससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिली है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन, लगातार हो रहे हादसे चिंता बढ़ाते हैं। दर्शनार्थियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्थानीय लोग और चार धाम के तीर्थ पुरोहित भी सरकार व प्रशासन के सामने यह मामला उठा चुके हैं। लोगों का साफ कहना है कि हेली ऑपरेटर मनमानी करते हैं। खराब मौसम में और काफी नीचे से उड़ान भरना आम है। वे यात्रियों की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, उनके नीचे उड़ने से लोगों के घरों पर भी खतरा पैदा हो गया है। इसका असर वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद से 10 जून तक, 9 हेली ऑपरेटरों ने 8 हजार 377 बार उड़ान भरी। सबसे ज्यादा यात्री ट्रांस भारत कंपनी से और सबसे कम क्रिस्टल एविएशन से केदारनाथ गए। ऑपरेटरों ने औसतन प्रतिदिन 215 शटल किया। हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए यह संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा, हेलिकॉप्टर पर क्षमता से अधिक वजन डाला गया। नियमों के अनुसार, वजन 250 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर यह 400 से भी अधिक हो गया। इतना ही नहीं, 7 जून को 253 शटल में 1484 यात्री केदारनाथ गए - यानी एक हेलिकॉप्टर से पायलट सहित 6 यात्रियों ने यात्रा की। ज्यादातर कंपनियों के पास सिंगल इंजन हेलिकॉप्टर हैं। हालांकि अब सरकार ने डबल इंजन वाले चॉपर ही इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। दरअसल, चार धाम में हेली ऑपरेटरों पर अंकुश के लिए ठोस नियमावली नहीं बनाई गई है। कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं। हालिया हादसों के बाद सरकार ने रवैया सख्त किया है, देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है।

एकदा

इनक्यूबेटर डॉक्टर

बात 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत की है। उन दिनों समय से पहले पैदा हुए बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों और आम लोगों के बीच धारणा बन चुकी थी कि प्रीमच्योर बेबी कुछ समय बाद जीवित नहीं रह पाते। एक दिन पोल्ट्री किसान को एक गर्म बक्से में अंडों को सेते हुए देख एक व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि जब अंडों को गर्म रखकर चूजों में बदला जा सकता है, तो शायद समय से पहले जन्मे शिशुओं को भी ऐसी गर्माहट और सुरक्षा देकर बचाया जा सकता हो। इस सोच को लेकर उन्होंने प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पियरे बुडिन के साथ काम शुरू किया। उन्होंने ऐसे शिशुओं को बचाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इसके लिए नर्सों को प्रशिक्षित किया। शुरुआत में लोग इस प्रयोग का मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आई, और माताएं अपने समय से पहले जन्मे शिशुओं को बचाने की उम्मीद में उनके पास छोड़ने लगीं। यह करिश्मे से कम नहीं था कि इनक्यूबेटर और नर्सों की मदद से उन्होंने लगभग सात हजार बच्चों की जान बचाई। समय के साथ इनक्यूबेटर अस्पतालों का जरूरी हिस्सा बन गया। इस महान कार्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे मार्टिन आर्थर कौनी, जिन्हें आज इनक्यूबेटर डॉक्टर के नाम से जाना जाता है।

Subrata Dhar

संकलन : रेनू सैनी

देश में हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के उपायों पर करना होगा विचार

पायलटों के हालात पर नहीं होती बहस

मनोज हाथी

हर हवाई हादसा पायलटों की भूमिका पर तीखे सवाल खड़े कर देता है, लेकिन कभी इस पर चर्चा नहीं होती कि पायलटों का काम कितना जटिल और चुनौती भरा होता है। उन्हें इंसानी दक्षता और तकनीकी उलझनों की कैसी मुश्किल रस्साकशी के बीच सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में वे फैसले करने पड़ते हैं, जिन पर सैकड़ों जिंदगियां निर्भर करती हैं।

कॉकपिट तक का सफर । किसी एयरलाइन के कॉकपिट तक की यात्रा सच पूछिए तो सबसे कठिन और थका देने वाली प्रफेशनल यात्राओं में आती है। बड़े विमानों तक पहुंचने के लिए कमर्शल पायलटों को 1500 से 4000 घंटों की उड़ान का अनुभव लेना होता है। लेकिन उसके बाद भी सीखने की यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। नियमों के मुताबिक, छह से 12 महीनों के अंतराल पर उन्हें विस्तृत प्रशिक्षण से अनिवार्य तौर पर गुजरना होता है। एक तो एविएशन टेक्नॉलजी लगातार उन्नत होती रहती है और दूसरे इंसानी दक्षता को भी निरंतर मांजते रहने की जरूरत होती है।

क्या है सचाई

- अनियमित शेड्यूल शरीर की लय बिगाड़ देते हैं
- हादसे टल जाएं तो भी उनका ट्रॉमा बना रहता है
- व्यवस्थागत त्रुटियां दूर करने पर बढ़े जोर

कल्पना से परे हालात । सिमुलेटर सेशंस यानी अभ्यास सत्रों के दौरान पायलटों को खराब मौसम से लेकर मल्टिपल सिस्टम फेल्यर और मेडिकल इमर्जेंसी तक - हर तरह की चुनौतियों से सामना कराया जाता है। मकसद होता है कि अत्यधिक तनाव की स्थितियों में सही फैसले करने और प्राथमिकताएं तय करने की उनकी क्षमता को परखा जाए। फिर भी, वास्तविक जिंदगी में पायलटों को इन सिमुलेटर सेशंस से बहुत आगे की और कई बार अकल्पनीय स्थितियों से निपटना पड़ता है।

रोटेशन का मसला । 1993 में एक बार जब मैं एयर इंडिया बोइंग 747 पर कमांडर था, ऐसी ही एक घटना हुई। एक पूरी तरह भरे बोइंग 737-200 ने टेक-ऑफ रन शुरू किया और रनवे के आखिरी सिरे पर कॉटन लदी एक लॉरी से टकराकर हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में 55 लोग मारे गए, 63 किसी तरह बचाए गए। अंतिम जांच रिपोर्ट में रोटेशन शुरू करने में हुई देरी और फ्लाइट आवर्स के दौरान रनवे पर ट्रैफिक रोकने में ग्राउंड टीम की नाकामी को संभावित कारण बताया गया था।

दो सेकंड की देर । रिपोर्ट के मुताबिक, 'लॉरी पर ध्यान जाने के बाद पायलट हड़बड़ा गया, उसने दो सेकंड तक कुछ नहीं किया और उसके बाद तेजी से ओवर-रोटेशन शुरू कर दिया।' पायलट की दृष्टि से यह 'तेज ओवर-रोटेशन' का मामला नहीं था। दो सेकंड की देर बहुत ज्यादा होती है। हर पायलट यह जानता है कि सही समय पर रोटेट करना है। हम सब ऐसा करते ही हैं। लेकिन, एक छोटी सी चूक और 55 जिंदगियां खत्म।

कामयाबियां कम नहीं । ऐसे नायक भी कम नहीं, जिन्होंने इन चंद सेकंड्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर सिचुआन एयरलाइंस के कैप्टन लिउ चुआन्चियान को लीजिए। 2018 में उनकी एयरबस ए 319 की खिड़की का शीशा 32000 फीट की ऊंचाई पर उखड़ गया था। उस विषम स्थिति में उन्होंने मैनुअली संचालित करते हुए 119 यात्रियों वाले उस विमान को सुरक्षित उतार लिया।

फ्लाइट में टूटी खिड़की । ऐसा ही एक और मामला कैप्टन टैमी जो शुल्ज का है। बोइंग 737 का एक इंजन फैन ब्लेड टूट गया और बाईं तरफ विमान के धड़े और एक खिड़की से टकराया। टूटी खिड़की से एक यात्री आंशिक रूप से बाहर खिंच गया, जिसे बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इन सबके बीच असामान्य कुशलता का परिचय देते हुए लेडी कैप्टन शुल्ज ने विमान की सेफ लैंडिंग कराई।

NBT आमने-सामने

कड़वी हकीकत । चमक-दमक के पीछे छिपी इस पेशे की कड़वी हकीकत यह है कि 78 फीसदी पायलट खुद को बुरी तरह थका हुआ बताते हैं, 22 फीसदी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और 12 फीसदी में एंग्जाइटी के लक्षण हैं। अनियमित ड्यूटी आवर्स के चलते शरीर की आंतरिक लय बिगड़ जाती है। हादसे टल जाएं तो भी उनका ट्रॉमा लंबे समय तक बना रहता है।

क्या है विरोधाभास । आधुनिक विमानों में बैठे पायलटों को आधुनिकतम तकनीकों से पूरी तरह अवगत होते हुए मैनुअल फ्लाइंग स्किल पर भी पकड़ बनाए रखनी होती है, जिसका इस्तेमाल करने का मौका उन्हें शायद ही कभी मिलता है। वे ऐसी जटिल स्वचालित व्यवस्था संचालित करते हैं, जो अप्रत्याशित रूप से कभी भी नाकाम हो सकती है।

व्यवस्था में सुधार हो । एविएशन इंडस्ट्री को व्यवस्थागत त्रुटियों पर काम करते रहना होगा, चाहे वे विमानों की डिजाइन से जुड़ी हों या एयरपोर्ट प्रबंधन से या फिर शेड्यूलिंग के तरीकों से। आखिर मामला उस प्रफेशन को सपोर्ट करने का है जहां हीरोइज्म अपवाद नहीं बल्कि रोजाना की जरूरत है।

(लेखक एयर इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं)

हादसे से बहुत कुछ सीख सकता है भारत

राकेश शुक्ला

भारत में 12 जून की दोपहर त्रासदी लेकर आई। अहमदाबाद के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 'फ्लाइटराडार 24' के आंकड़ों के अनुसार, विमान ने ऊंचाई खोने से पहले 322 किमी प्रति घंटे की जमीनी गति से 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की सूचना दी थी।

इमेज को धक्का । हादसे का शिकार हुआ बोइंग 787 अमेरिकी विमान कंपनी का सबसे आधुनिक वाइड-बॉडी जेट है। दुर्घटना ऐसे वक्त हुई, जब कंपनी अपने नैरो बॉडी 737 मैक्स 8 से जुड़े हादसों के कारण प्रतिष्ठा को हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह, एयर इंडिया भी निजीकरण के बाद से अपनी इमेज सुधारने के प्रयास में है। पहले यह एयरलाइंस सेवा में देरी और उदासीनता के लिए जानी जाती थी। 2022 में इसका निजीकरण कर दिया गया और अब इसका नियंत्रण टाटा समूह के पास है। तब से एयरलाइंस अपनी सेवाओं में लगातार सुधार कर रही है।

हवाई सेवा का विस्तार । हाल के वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र में तेजी से उछाल आया है। हवाई अड्डों, यात्रियों और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय - दोनों मार्गों की संख्या में तेज गति से विस्तार हुआ है। पिछले दशक में गुजरात के राजकोट सहित कई भारतीय शहरों में आधुनिक हवाई अड्डे खोले गए।

अच्छा रेकॉर्ड । भारतीय विमानन उद्योग को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी सूचकांक में भारत की रेटिंग वैश्विक औसत से ऊपर है। हालांकि यह अब भी पश्चिमी देशों और चीन से पीछे है। इसके बावजूद, भारत का आपदाओं से सीखने और बदलाव का रेकॉर्ड सराहनीय रहा है।

सेक्टर में मौके । करीब 18 साल पहले शुरू हुई इंडिगो आज भारतीय विमानन बाजार में अग्रणी है। इसके पास दुनिया की किसी भी बड़ी एयरलाइन के मुकाबले सबसे युवा बेड़ा है। इसके विमानों की औसत आयु लगभग 4 साल है। वहीं, एयर इंडिया का बेड़ा लगभग दोगुना पुराना है। हालांकि नए विमानों की डिलिवरी के साथ उसमें भी बदलाव दिखेगा। कुछ दिनों पहले भारत में आयोजित इंटरनैशनल एयर ट्रांसपोर्ट असोसिएशन की वार्षिक बैठक में बताया गया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। अनुमान है कि तेजी से बढ़ती मांग के चलते भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।

बढ़ रहे यात्री । हवाई यात्रा को लेकर भारतीयों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। 2019 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 13.7 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 22.8 करोड़ से भी अधिक हो गई है। कोरोना महामारी से पहले देश में घरेलू रूटों पर 646 विमान संचालित हो रहे थे। मार्च 2023 तक यह संख्या 823 हो गई थी। आय बढ़ने के साथ ही हवाई यात्रा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

सुधार की जरूरत

- सबसे तेजी से बढ़ रहा भारत का विमानन सेक्टर
- घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या व रूट में बढ़ोतरी
- इंटरनैशनल रेटिंग में अब भी चीन से पीछे भारत

ग्लोबल सेंटर । भारत को सरकार ग्लोबल एविएशन सेंटर बनाना चाहती है, यानी यूरोप, पूर्वी एशिया या अफ्रीका से उत्तर एशिया जाने वाले यात्री सिंगापुर या दुबई के बजाय दिल्ली या मुंबई में विमान बदलें। एयरलाइंस के लिए इसका मतलब सिर्फ नए चमकदार हवाई अड्डे और अच्छी सेवा प्रदान करना ही नहीं, वैश्विक यात्रियों का भरोसा भी जीतना है कि भारत बिल्कुल सुरक्षित है। अहमदाबाद जैसे हादसे कुछ समय के लिए इस महत्वाकांक्षा पर सवाल खड़े करेंगे।

ड्रीमलाइनर का इतिहास । बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की शुरुआत 26 अप्रैल 2004 को हुई, जब जापान के ऑल निप्पन एयरवेज (ANA) ने इसके 50 विमानों का पहला ऑर्डर दिया। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 15 दिसंबर 2009 को भरी और अक्टूबर 2011 में इसे व्यावसायिक सेवा में शामिल किया गया। फिलहाल दुनियाभर में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लगभग 1,189 विमान सेवा में हैं। अधिकांश विमानों को जापान एयरलाइंस, ANA, एयर इंडिया, कतर एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस जैसी प्रतिष्ठित एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जा रहा है।

आधुनिक तकनीक । ड्रीमलाइनर अपनी उन्नत तकनीक और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसका ढांचा कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलिमर से बना है। यह सामग्री हल्की होने के साथ मजबूत भी है। इससे विमान का वजन कम रहता है, ईंधन की खपत पारंपरिक विमानों की तुलना में 20% तक कम होती है। ड्रीमलाइनर की खिड़कियां पारंपरिक विमानों के मुकाबले बड़ी होती हैं।

सीखने की जरूरत । दुनिया की कुछ ऐसी एयरलाइंस भी हैं - जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास, दुबई की एमिरेट्स और अमेरिका की अलास्का, जिनके पास हजारों विमानों का बेड़ा है और हर साल करोड़ों यात्री इनमें सफर करते हैं। दशकों के इतिहास में आज तक एक भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। हमें उनसे सीखने की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और हवाई मामलों के जानकार हैं)

बाल फ़िल्मों में पीछे क्यों है बॉलिवुड

रेखा खान

हाल ही में बच्चों की एक फिल्म देखी, 'चिड़िया'। जीवन की विसंगतियों के बीच सच्ची, सरल और दिल को छूने वाली बालसुलभ कहानी एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। दुनियाभर के कई प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में सराही गई 'चिड़िया' ने भारत में भी समीक्षकों और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। मगर हमारे यहां बच्चों की फिल्में इतनी कम क्यों बनती हैं?

पुराने हालात । दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। भारतीय सिनेमा 111 साल का बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन बाल फिल्म बनाने के मामले में अब भी बच्चा ही है। समय के साथ सिनेमा में तकनीक, कहानियां, विषय - सब कुछ बदलता चला गया, लेकिन बाल फिल्मों के हालात नहीं बदले। वे पहले भी कम बनाई जाती थीं और आज भी कम बनाई जाती हैं।

गहरी छाप । कमाल की बात यह है कि गिनती की होने के बावजूद इन फिल्मों का असर बहुत गहरा है। तारे जमीन पर, सीक्रेट सुपर स्टार, स्टेनली का डब्बा, धनक, निल बटे सन्नाटा, जजंतरम ममंत्रम, चिल्लर पार्टी, छोटा चेतन, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों ने बच्चों के साथ बड़ों को भी लुभाया है। पहले के दशकों में बूट पॉलिश, काबुलीवाला, ब्रह्मचारी, दो कलियां, मासूम जैसी फिल्मों ने बच्चों के मासूम मनोविज्ञान पर छाप छोड़ी।

यादगार काम । बॉलिवुड में बच्चों की मौजूदगी अक्सर सबप्लॉट या गानों के बहाने होती है। पूरी फिल्म को बच्चों के नजरिए से कहना अब भी फिल्मकारों के लिए 'टेढ़ी खीर' है। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नाम जरूर रहे, जिन्होंने बाल मन को खंगाला। इनमें गुलजार ने 'परिचय' और 'किताब' जैसी फिल्मों में बच्चों की भावनाओं को सहजता से दर्शाया। विशाल भारद्वाज ने 'ब्लू अम्ब्रेला' और 'मकड़ी' में बच्चों की कल्पना और डर की दुनिया को छूने का साहस दिखाया। आमिर खान 'तारे जमीन पर' से डिस्लेक्सिया जैसे संवेदनशील विषय को केंद्र में लेकर आए। वहीं अमोल गुप्ते की स्टेनली का डब्बा एक असर छोड़ने वाली फिल्म थी। अगर बंगाली सिनेमा की बात करें, तो सत्यजीत रे ने बाल फिल्मों की जो विरासत दी, वह आज भी मिसाल है।

कॉमन रूम

उदासीनता की वजह । सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कहलाने वाला भारत बाल फिल्मों को लेकर इतना उदासीन क्यों है? वजह साफ है, हमारे देश में फिल्मकार बच्चों को सीरियस ऑडियंस नहीं मानते। अभिभावकों को लगता है कि बच्चों को अगर कुछ दिखाना है, तो घर पर ही टीवी पर दिखाया जा सकता है।

रिलीज में मुश्किल । आज सफलता का पैमाना करोड़ों की कमाई है और बाल फिल्में इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठतीं। उन्हें 'चिल्ड्रेन फिल्म' का तमगा देकर अलग-थलग कर दिया जाता है। कोई जाना-माना चेहरा न हो तो रिलीज में बरसों लग जाते हैं। मेहरान अमरोही निर्देशित 'चिड़िया' को सिनेमाघरों तक पहुंचने में पूरे 10 साल लगे। बकौल मेहरान, 'लोग कहते, फिल्म अच्छी है, लेकिन बिकाऊ चेहरा नहीं।' और अगर रिलीज हो भी जाए, तो बड़ी फिल्मों के बीच थिएटर तक मिलना मुश्किल हो जाता है। 1955 में बच्चों को उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन देने के लिए 'बाल चलचित्र समिति' बनाई गई थी, पर वह बीते बरसों में कोई कमाल न कर सकी।

हॉलिवुड से सीखें । देश में बच्चों की फिल्मों का मार्केट है, तभी 'हैरी पॉटर' या 'होम अलोन' जैसी हॉलिवुड फिल्में यहां आकर रेकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं। हम बजट में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन 'स्टेनली का डिब्बा' सरीखी मासूम कहानी जरूर बना सकते हैं।

सितारों का साथ । ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब बच्चों की फिल्मों को बड़े सितारों का साथ मिला, तो दर्शकों ने खुलकर सराहा। 'भूतनाथ' में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, 'तारे जमीन पर' में आमिर खान, 'मकड़ी' में शबाना आजमी, 'मिस्टर इंडिया' में अनिल कपूर-श्रीदेवी - इन सभी उदाहरणों ने यह साबित किया है कि स्टार पावर से बच्चों की फिल्में भी मुख्यधारा में जगह बना सकती हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ सुरक्षा के लिए नियम

17 जून का संपादकीय 'मानकों की अनदेखी' पढ़ा। उत्तराखंड में पिछले दो महीने में पांच हेलिकॉप्टर हादसे हुए। यदि पहले हादसे के बाद ही सतर्कता और मॉनिटरिंग तेज की जाती, तो शायद बाद वाले चार हादसे नहीं होते। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में हेलिकॉप्टर सेवा को संबंधित तीर्थ यात्रा बोर्ड नियंत्रित करते हैं जबकि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का चारधाम हेलिकॉप्टर यात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं है। यात्रा बुकिंग आईआरसीटीसी के अलावा हेलिकाप्टर संचालक स्वयं भी करते हैं। इस तरह लगभग पूरी तरह से निजी क्षेत्र के रहमो-करम पर होने के कारण यहां दुर्घटनाओं की आशंका जताई जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाए।

बृजेश माथुर, क्रॉसिंग रिपब्लिक

■ अमेरिका में संघर्ष

यह पत्र 17 जून को प्रकाशित लेख 'LA की गलियों में हो रही सियासी जंग' से संबंधित है। तो अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मुद्दा अब कानून व्यवस्था से आगे बढ़ चुका है। इसने राजनीतिक और मानवीय बहस का रूप ले लिया है। कैलिफोर्निया जैसे प्रगतिशील राज्य का ट्रंप की नीतियों को अपनाना बहुत मुश्किल है। आने वाले वक्त में टकराव बढ़ सकता है।

कृतिका झा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

ट्रंप ने कहा, ईरान और इस्राइल में समझौता करा सकता हूं - एक खबर
- पहले यूक्रेन और रूस में तो समझौता करा लें!

जितेन्द्र अहलावत

सांसारिक जीवन में रहते हुए भी प्रभु को पाना संभव

स्वामी मुकुंदानंद

आज के भौतिकवादी युग में जब जीवन की दौड़ और सामाजिक दबाव हावी हैं, तब धर्म को समझना व उसे अपनाना कठिन लगता है। अगर हम सही सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करें, तो अराजकता के बीच भी शांति और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। 'धर्म' शब्द का कोई सटीक अंग्रेजी पर्याय नहीं। यह संस्कृत की 'धृ' धातु से बना है। इसका अर्थ है - 'धारण करने योग्य'। धर्म का तात्पर्य ऐसे आचरण, मूल्यों और सिद्धांतों से है, जिन्हें जीवन में धारण किया जा सके। भगवद्गीता के अनुसार, धर्म को भगवान स्वयं स्थापित करते हैं और बड़े-बड़े ज्ञानी, संन्यासी, मुनि भी पूरी तरह इसे नहीं समझ पाते। धर्म के स्वरूप को हम इस तरह से समझ सकते हैं।

धर्म के स्वरूप को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है - भौतिक यानी सामाजिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। सामाजिक धर्म हमारे सांसारिक कर्तव्यों से जुड़ा है - परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का पालन। प्राचीन भारत में इसे 'वर्णाश्रम धर्म' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और क्षमताओं पर आधारित था, न कि जन्म पर। हालांकि आज उसका स्वरूप बदल गया है, पर इसका मूल उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना था। ये कर्तव्य आवश्यक हैं, पर केवल इनसे आत्मा की परम संतुष्टि नहीं होती।

आध्यात्मिक धर्म आत्मा के शाश्वत कर्तव्यों से जुड़ा है। जब हम स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा मानते हैं, तब हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है। भगवद्गीता में कहा गया है - सबसे बड़ा धर्म वह है, जो हमें भगवान के प्रति निष्काम भक्ति की ओर ले जाए। यह भक्ति ही आत्मा को शुद्ध करती है और भगवद् प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे नदी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव भी भगवान से मिलन की ओर होता है। सही मायने में देखा जाए तो यही मिलन परमानंद का स्रोत है।

लेकिन, आध्यात्मिक धर्म का यह अर्थ नहीं कि सामाजिक धर्म को नकार दिया जाए। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं - अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा स्मरण करो। यह कर्म योग का मार्ग है, जहां व्यक्ति सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आत्मा और परमात्मा के संबंध को जागरूकता के साथ निभाता है। धर्म का सच्चा रूप केवल किसी परंपरा को निभाने या डरकर उसका पालन करने से नहीं जुड़ा, यह अपने जीवन को सत्य, सेवा और भक्ति के सिद्धांतों से जोड़ना है। यही हमें बाहरी अराजकता के बीच भी आंतरिक शांति और जीवन के परम लक्ष्य यानी भगवद् प्राप्ति की ओर ले जाता है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

हर शहर जाम से परेशान क्यों है?

हमारे ज्यादातर शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। खासकर, शहर के कामकाजी समय में बेहिसाब भीड़भाड़ और जगह-जगह जाम से सब परेशान हो जाते हैं। पैसा, संसाधन और समय, तीनों की बर्बादी होती है। क्या सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार जरूरत के हिसाब से नहीं हो पा रहा है? पेश है, शहरों में सार्वजनिक परिवहन के हालात का जायजा लेती मनोज शर्मा की रिपोर्ट...

लगभग दस दिन पहले मुंबई में व्यस्ततम समय में भीड़भाड़ वाली लोकल रेल से गिरकर चार यात्रियों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए। मुंबई की जीवन रेखा कहलाने वाली लोकल रेल 2,500 यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है, पर व्यस्त समय में 5,000 से ज्यादा यात्रियों को ढोती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे हालात में मुंबई की पटरियों पर 2005 से 2024 के बीच 51,802 लोगों की जान गई है, मतलब औसतन एक दिन में सात मौतें। मुंबई ही नहीं, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में भी यात्री नियमित रूप से बसों में ठूंस-ठूंस कर जाते हैं और भीड़भाड़ वाले मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जगह के लिए धक्का-मुक्की करते हैं। यह संख्या अक्सर बसों और ट्रेनों की क्षमता से लगभग दोगुनी होती है। यह परिदृश्य हमारे महानगरों में सार्वजनिक परिवहन की भीड़भाड़ के बढ़ते संकट को उजागर करता है।

ओएमआई फाउंडेशन की 'ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022' की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, देश के 40 शहरों में सर्वेक्षण में शामिल लोगों में 25.17 प्रतिशत ने बताया कि बसें इतनी भीड़भाड़ वाली होती हैं कि उन्हें खड़े होने के लिए भी मुश्किल से जगह मिल पाती है। विशेषज्ञ बढ़ते संकट के लिए तेजी से हो रहे शहरीकरण, वाहनों की भारी कमी और असंतुलित सरकारी खर्च को दोषी ठहराते हैं। अक्सर उन शहरों में भी मेट्रो रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें उनकी जरूरत नहीं है।

यातायात विशेषज्ञ श्रेया गडेपल्ली कहती हैं, 'सार्वजनिक वाहनों में भारी भीड़ मांग और आपूर्ति के बीच के बढ़ते अंतर का परिणाम है। शहरी विकास में तेजी के बावजूद, सार्वजनिक परिवहन, खासकर बसों की संख्या नहीं बढ़ी है।'

नगरों में बस की कमी

देश के चार महानगरों - मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली में सार्वजनिक बसों में चिंताजनक गिरावट है। गडेपल्ली कहती हैं, 'उदारीकरण के बाद सरकार की प्राथमिकता में बस सेवा बहुत नीचे चली गई है। सरकारों ने इसके बजाय मेट्रो रेल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि बसों के बेड़े सिमटने लगे। वाहन पुराने हो गए। जैसे-जैसे सार्वजनिक वाहनों की विश्वसनीयता घटी, प्रतीक्षा का समय बढ़ता गया, वैसे-वैसे अधिकतर यात्री निजी कारों और दोपहिया वाहनों से चलने लगे। इससे सड़कों पर भीड़भाड़ और बढ़ गई।'

सरकारी बसें बेबस

मुंबई की अगर बात करें, तो बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की बसों की भारी कमी है। अभी सेवा में 2,591 बसें हैं। इनमें से केवल 434 (17 प्रतिशत) ही बेस्ट की हैं। बाकी बसें निजी ठेकेदारों के साथ वेट लीज समझौतों के तहत संचालित होती हैं। यहां एक दशक पहले 4,200 बसें चलती थीं। बेस्ट के अधिकारियों का कहना है कि हमने 100 नई बसों का ऑर्डर दिया है, जो एक महीने के भीतर आ जाएंगी। एजेंसी का लक्ष्य शहर के बेड़े में 2029 तक 6,000 बसें लाने का है।

कोलकाता का बुरा हाल

कभी ट्राम के लिए विख्यात कोलकाता में पिछले दशकों में ट्राम सेवा खत्म ही हो गई है। यहां 1970 के दशक में प्रतिदिन सात लाख से अधिक यात्री ट्राम से यात्रा करते थे। इंडिया क्लीन एयर नेटवर्क (आईसीएएन) और कोलकाता बस-ओ-पीडिया द्वारा मार्च 2025 के कम्प्यूटर सर्वेक्षण में पाया गया कि आधे यात्रियों को बस यात्रा में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती कहते हैं, '2009 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने का आदेश दिया था, इससे बसें हटानी पड़ीं।'

राष्ट्रीय राजधानी खस्ताहाल

दिल्ली भी बसों के कम होते बेड़े से जूझ रही है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खरीदी गई कई सीएनजी बसें चरणबद्ध तरीके से हटाई जा रही हैं और उनका खराब होना आम बात है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा 2024 के ऑडिट में पाया गया कि डीटीसी की बसें औसतन हर 12 दिन में एक बार खराब होती हैं। यह संख्या भारत के प्रमुख महानगरों की तुलना में सर्वाधिक है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के पास अभी लगभग 6,500 बसें हैं। डीटीसी के एक अधिकारी बताते हैं, 'साल के अंत तक 1,000 और बसें आने की उम्मीद है।' दिल्ली सरकार ने साल 2026 तक 10,000 बसों का लक्ष्य रखा है।

दिल्ली सरकार ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि परिवहन की मांगों को पूरा करने के लिए राजधानी को कम से कम 11,000 बसों की आवश्यकता है। गडेपल्ली कहती हैं, '1990 के दशक के अंत में दिल्ली में करीब 10,000 बसें थीं। आज इनकी संख्या बमुश्किल आधी रह गई है। इसकी तुलना बीजिंग से करें, जहां 28,000 से ज्यादा बसें चलती हैं।' गडेपल्ली बताती हैं, 'जरूरत है, ज्यादा बसों की, बेहतर बसों की और तेज बसों की। डेडिकेटेड बस लेन से गति और दक्षता में काफी सुधार हो सकता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में बसें एक दिन में 280 किलोमीटर तक चल जाती हैं, जबकि भारतीय महानगरों में औसतन 160-170 किलोमीटर। इससे सड़कों पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है।'

दिल्ली मेट्रो पर भार

भारत की सबसे उन्नत परिवहन प्रणाली मेट्रो भी दबाव में है। दिल्ली मेट्रो पीक ऑवर्स में खासकर राजीव चौक, हौज खास, लक्ष्मी नगर और चांदनी चौक जैसे व्यस्त यातायात वाले स्टेशनों पर गंभीर भीड़भाड़ से जूझती है। दिल्ली मेट्रो में रोजाना 70 लाख से अधिक लोग यात्रा करते हैं। कई स्टेशनों पर तो कतारें अक्सर सड़कों तक लग जाती हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के कॉरपोरेट संचार के प्रमुख कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल कहते हैं, 'आम तौर पर भीड़ पीक ऑवर्स के दौरान होती है, खासकर इंटरचेंज स्टेशनों पर। क्षमता बढ़ाने और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए व्यस्त लाइनों पर पीक टाइम के दौरान हर 2-3 मिनट में ट्रेनें चलानी पड़ती है।' उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीएमआरसी ने मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम, नई दिल्ली और कश्मीरी गेट सहित कई स्टेशनों पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया है। दयाल बताते हैं, 'हमने व्यस्त स्टेशनों पर कतार में लगने वाले समय को कम करने के लिए अधिक स्वचालित किराया संग्रह द्वार भी लगाए हैं और यात्रियों को आराम वाले समय में यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किराए में व्यस्त समय के दौरान 10 प्रतिशत और गैर-व्यस्त समय के दौरान 20 प्रतिशत की छूट शुरू की है।'

अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद (आईसीसीटी) के भारत में प्रबंध निदेशक अमित भट्ट का कहना है कि दिल्ली को अपने मौजूदा बस बेड़े को दोगुना करने और उसे मेट्रो नेटवर्क के साथ बेहतर एकीकरण करने की जरूरत है। वह बताते हैं, 'हमें यह समझना चाहिए कि एक बार जब लोग सार्वजनिक परिवहन से दूर हो जाते हैं, तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है।'

Hindustan Times

उत्तर प्रदेश

लखनऊ

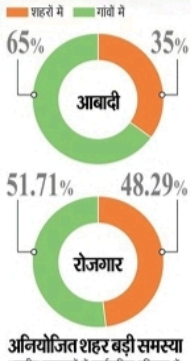

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आबादी बढ़ रही है और सार्वजनिक वाहन कम पड़ते जा रहे हैं। तेजी से फैल रहे लखनऊ की आबादी 50 लाख के आसपास है। यहां हर दिन लगभग 3.10 लाख लोग सार्वजनिक वाहनों से सफर करते हैं, जबकि औसतन दो लाख लोग हर दिन ऑटो-टेंपो, ई-रिक्शा से सफर करते हैं। अब सबसे ज्यादा यात्री मेट्रो से सफर करने लगे हैं। शहर में 21 रूटों पर 155 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। सिटी बसों से लगभग 29 से 30 हजार लोग हर दिन सफर करते हैं। शहर में जाम की स्थिति बढ़ रही है, क्योंकि निजी वाहनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।

बिहार

पटना

बिहार की राजधानी पटना में भीड़भाड़ बढ़ती जा रही है। करीब 27 लाख की आबादी वाले इस शहर में सार्वजनिक वाहनों की सुविधा पर्याप्त नहीं है। कुल 460 बसों का परिचालन होता है, इनमें 208 बसें ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की हैं, बाकी निजी हैं। शहर में दौड़ रही पिंक बसों की संख्या दस है। पिंक बसों में सिर्फ महिलाएं सफर करती हैं, इनमें कंडक्टर महिलाएं ही होती हैं। पटना मेट्रो रेल सेवा के स्वागत के लिए भी तैयार है। पहले चरण में प्राथमिक कॉरिडोर में 15 अगस्त 2025 से 6.1 किलोमीटर लंबी लाइन पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। साल 2019 में मेट्रो परियोजना शुरू हुई थी, वर्ष 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखंड

रांची

झारखंड की राजधानी रांची की करीब 15 लाख आबादी के आवागमन के लिए सिटी बस, ऑटो और ई-रिक्शा ही सहारा है। शहर में करीब 20 हजार ऑटो चलते हैं। नगर निगम के पास 41 सिटी बसें हैं, जिनमें 15 अनफिट हैं। 26 बसें ही चल रही हैं। एक ही रूट पर बस चलने से अन्य मार्ग पर ऑटो और ई-रिक्शा पर निर्भरता है। 12 हजार ई-रिक्शा चल रहे हैं। शहर में पार्किंग, ऑटो और सिटी बसों का स्टैंड भी निर्धारित नहीं है। बसें और ऑटो जहां-तहां रुकते हैं और जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। शहर के मुख्य मार्गों पर हमेशा जाम लगा रहता है। फिलहाल, रांची समेत झारखंड के किसी भी शहर में मेट्रो चलाने की कोई योजना नहीं है।

उत्तराखंड

देहरादून

बारह लाख से अधिक आबादी वाले देहरादून में सार्वजनिक परिवहन पुराने ढर्रे पर चल रहा है। यहां बाहर से आने वाली आबादी का भी बहुत दबाव है। डेढ़ सौ सिटी बसें संचालित हो रही हैं, जो खटारा स्थिति में हैं। धुंआ छोड़ते और ठूंस कर भरी सवारियों को लेकर चलते विक्रमों की संख्या 400 के लगभग है, लेकिन शहर में एक-स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए इन्हें दो से तीन बार बदलना पड़ता है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महज 30 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। यहां सार्वजनिक परिवहन बहुत महंगा भी है। यहां मेट्रो चलाने के नाम पर आठ साल में 90 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब तक जमीन पर एक इंच भी काम नहीं दिखता है।

शहरों पर ज्यादा दबाव

अनियोजित शहर बड़ी समस्या

भारतीय महानगरों में सार्वजनिक परिवहन में लगातार भीड़भाड़ सिर्फ परिवहन की समस्या नहीं है, बल्कि शहरों के अनियोजित विकास का नतीजा है। कई भारतीय शहरों में जनसंख्या वृद्धि बुनियादी ढांचे के विकास से कहीं आगे निकल गई है और परिवहन प्रणाली इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है। ध्यान रहे, देश में बेंगलुरु, पुणे के प्रति बहुत आकर्षण है, पर ये देश के सबसे घने या कंजेस्टेड शहरों में गिने जाते हैं।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। कारोबार के लिए विदेश जा सकते हैं। यात्रा लाभप्रद।

वृष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। भवन सुख में वृद्धि होगी। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परंतु मन परेशान भी हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी बढ़ेगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।

कर्क : मन में निराशा और असंतोष रहेगा। संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में विस्तार हेतु निवेश कर सकते हैं।

सिंह : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। माता का सान्निध्य मिलेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। सेहत पर ध्यान दें।

तुला : कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार के बुजुर्ग से धन प्राप्ति हो सकती है।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। कारोबार में यात्रा लाभप्रद रहेगी।

धनु : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

मकर : मन परेशान रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में बदलाव हो सकता है।

कुंभ : मन प्रसन्न रहेगा। किसी पुराने मित्र का आना हो सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि होगी। भाग-दौड़ अधिक रहेगी। कारोबार हेतु यात्रा लाभप्रद रहेगी।

मीन : मन परेशान हो सकता है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

18 जून, बुधवार, शक संवत् : 28 ज्येष्ठ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 04 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 21 जिल्हिजा, 1446, विक्रमी संवत : आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 01.35 मिनट तक पश्चात् अष्टमी तिथि। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 12.23 तक। प्रीति योग प्रात: 07.40 बजे तक पश्चात आयुष्मान योग सूर्योदय पूर्व 5.24 बजे तक, चंद्रमा कुंभ राशि में सायं 06.35 मिनट तक उपरांत मीन राशि।
सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। कुछ सालों से दुकान का ग्राफ नीचे ही जा रहा है, खासकर जबसे इसका विस्तार किया है। कृपया कोई उपाय बताएं। - प्रीत, बनारस

- आपने अपनी दुकान का विस्तार दक्षिण दिशा में किया है, जो शुभ नहीं माना जाता है। पहली तथा दूसरी मंजिल पर दक्षिण वाली दिशा में माल रखने के कारण फर्श नीचा कर दिया है। यह आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण है। इसको प्राथमिकता के तौर पर भरें, वरना समस्या और बढ़ सकती है। आपके काउंटर के ऊपर बीम आ रहा है। इससे कार्य एवं धन आगमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपना काउंटर बीम से बाहर निकालें या बीम पर वास्तु उपाय के अनुसार बांसुरी लगाएं।

वर्ग पहेली : 8000

बाएं से दाएं
1. जर्जर कर देना; बहुत स्थानों पर छेद कर देना (3,2,3)
6. करुणा; दया; रहम (3)
7. शंख कमल; जल में उत्पन्न होने वाला (3)
8. हाथ की गदोरी; हथेली; हस्त तल (4)
10. स्वीकार होना; स्वीकृत होना (4)
13. कन्या; पुत्री; बेटी; लड़की; गंगा; दुर्गा (3)
14. उलझन वाली स्थिति; कठिनाई; जटिल विषय (3)
16. अदब से चलना; विनीत भाव से चलना; प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहते हुए चलना (2,1,2,3)

ऊपर से नीचे
2. बलखाता हुआ; लहराता हुआ; जोशीला (5)
3. अल्पता; टोटा; दुर्लभता; न्यूनता; कोताही; त्रुटि; भूल; घाटा; हानि; दुर्गुण (2)
4. लज्जाप्रद; शर्मनाक; शर्मिंदा करने वाला (5)
5. लड़ना; झगड़ा करना (4)
7. आब; नीर; पानी; सलिल (2)
8. अट्टहास; जोर की हंसी; ठहाका (4)
9. उत्तरकाल में; उसके उपरांत; उसके बाद (5)
11. कृपालु; दयालु (5)
12. पिता की सास; मां की मां (2)
15. नुकीली वस्तु के चुभने जैसी पीड़ा; बड़ा, लंबा और नुकीला कांटा; वायु प्रकोप से होने वाला तेज दर्द (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 7999

1 स	■	2 र	■	3 रा	ज	4 कु	मा	5 र
6 प	र	ज	मा	ई	■	पि	■	सि
न	■	नी	■	का	■	7 त	नि	क
■	■	8 च	ट	प	टा	■	■	ज
9 म	धु	र	■	हा	■	10 ध	म	न
नो	■	■	11 अ	ड़	दा	र	■	■
12 रं	ज	13 के	■	ब	■	प	■	14 शी
ज	■	य	■	15 ना	ट	क	क	मी
16 न	शा	च	ढ़	ना	■	ड़	■	ला

सुडोकू : 7982

* मध्यम

		6				9		
	7			4			8	
1	2						5	6
		9	4		2	3		
			3		8			
		8	7		5	2		
8	1						9	4
	6			7			2	
		2				6		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 7981

2	9	5	6	1	8	3	7	4
1	8	6	4	7	3	9	5	2
3	7	4	9	5	2	8	1	6
4	2	9	5	3	1	7	6	8
7	6	3	8	4	9	5	2	1
8	5	1	2	6	7	4	9	3
5	1	8	7	2	4	6	3	9
9	3	7	1	8	6	2	4	5
6	4	2	3	9	5	1	8	7

जनगणना की अधिघोषणा

महत्वपूर्ण कदम

जनगणना 2027 की अधिघोषणा समावेशी भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 16 जून, 2025 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक रूप से भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की अधिघोषणा जारी कर दी। स्वतंत्रता के बाद से यह आठवीं जनगणना होगी जो देश के इतिहास में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनसंख्यात्मक कार्य है। लेकिन यह केवल परिवारों और लोगों की एक और गणना ही नहीं है। पहली बार भारतीय जनगणना में जातियों का आंकलन भी होगा। इस कदम के नीति निर्माण, प्रशासन तथा राजनीतिक विमर्श पर संभावित परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेंगे। मूलत: 2021 में निर्धारित, जनगणना 2027 छ: साल के विलंब के बाद हो रही है जिसका कारण मुख्यत: कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा उसके कारण लंबे समय तक जमीनी कार्रवाइयों में आई बाधा है। इसके साथ ही जाति गणना के मुद्दे पर राजनीतिक संवेदनशीलता तथा प्रशासनिक हिचक ने भी इस राष्ट्रीय परिवर्तन में योगदान दिया। बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023 ने इस राष्ट्रीय परिवर्तन में जमीनी भूमिका अदा की। इसके परिणामों को लंबे समय से व्याप्त अनुमानों के आधार पर चुनौती दी गई तथा इससे व्यापक राष्ट्रीय विमर्श का जन्म हुआ। महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा अपने सर्वेक्षण कराने के साथ ही केन्द्र सरकार पर राजनीतिक हिचक तोड़ने के लिए दबाव बना। पिछले कुछ वर्षों से जाति-आधारित डेटा का समावेशन गरमागरम चर्चा का विषय रहा है। विपक्ष लगातार जाति-आधारित जनगणना की मांग करता रहा है ताकि सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं की बेहतर समझदारी हो सके और ज्यादा लक्षित कल्याणकारी नीतियां बनाई जा सकें। लेकिन मोदी सरकार लंबे समय से यह कह कर इन मांगों से असहमति व्यक्त कर रही थी कि जाति गणना विभाजनकारी और लाजिस्टिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों व कुछ एनडीए पार्टियों के बढ़ते दबाव व खासकर 2023 में बिहार में जातीय सर्वेक्षण को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अंतत: इसे स्वीकार कर लिया।

पहली बार जनगणना का पूरा कार्यक्रम डिजिटल होगा। इसमें लगभग 34 लाख आंकलनकर्ता व 1.3 लाख कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा जो क्षमता, सटीकता तथा तत्काल डेटा प्रबंधन के लिए मोबाइल अप्लीकेशनों का प्रयोग करेंगे। जनगणना, 2027 का महत्वपूर्ण तत्व डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से आत्म-आंकलन का विकल्प होगा जिससे नागरिक सीधे डेटा संग्रह प्रक्रिया में भागीदार बन सकेंगे। इससे जनगणना में आम लोगों की उत्साही सहभागिता सुनिश्चित होगी। जाति संबंधी आंकड़ों का जनगणना में शामिल करना एक आमूलचूल परिवर्तन का प्रारंभ है।

दशकों से भारतीय नीति निर्माता अधूरे जातीय आंकड़ों का प्रयोग कर रहे थे जो 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित थे। आधिकारिक रूप से इसी साल अंतिम जातीय जनगणना हुई थी। इस प्रकार पुरानी पड़ चुकी तस्वीर के आधार पर विरोधाभासी नीतियां बनाई गईं, कल्याणकारी कार्यक्रमों को आधे-अधूरे ढंग से लक्षित किया गया तथा असंगत आरक्षण ढांचों का प्रयोग हुआ। सभी प्रकार की राजनीतिक पार्टियां, खासकर विपक्षी पार्टियों ने तर्क दिया था कि बिना सटीक जाति-आधारित आंकड़ों के सकारात्मक कार्रवाई तथा सामाजिक-आर्थिक योजनाओं से समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित नहीं हो सकता है। विडंबना है कि भारत में जाति के कारण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्यरक्षा और भूमि स्वामित्व तक पहुंच प्रभावित होती है। ऐसे में विस्तृत जनगणना से डेटा-संचालित सामाजिक न्याय नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी तथा आवश्यक होने पर आरक्षण सीमाओं को पुन: निर्धारित किया जा सकेगा। इससे संसाधनों का समाज कल्याण में ज्यादा प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित होगा। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जनगणना 2027 भारतीय समाज का एक आईना हो सकती है। इससे पहली बार नीति निर्माताओं और नागरिकों को विश्वसनीय व बहुआयामी जाति संबंधी आंकड़ों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे लक्षित कल्याण, सामाजिक सुधार और सहभागी प्रशासन की नई संभावनायें बनेंगी। हालांकि, इसमें डेटा की निजता, राजनीतिक दुरुपयोग, प्रशासनिक गलतियां जैसी चुनौतियां हो सकती हैं, पर इससे अनेक लाभ मिलने की संभावना बहुत अधिक है।

भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान

पवित्र मंदिरों की बहाली, तीर्थयात्रा मार्गों में सुधार, प्राचीन विलुप्त कलाकृतियों की खोज तथा भारत की आध्यात्मिक राजनय को पुनर्जीवित कर सरकार ने भारत की पहचान में गहरे गौरव की भावना पुनर्जीवित की है।

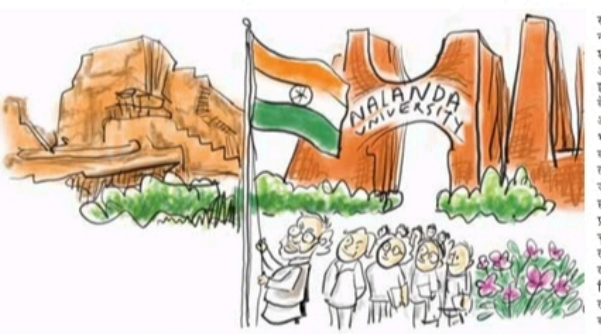

कौशल कांत मिश्रा
(लेखक, मंदिरों के पुनरुत्थान से संबद्ध हैं)

पवित्र मंदिरों की बहाली, तीर्थयात्रा मार्गों में सुधार, प्राचीन विलुप्त कलाकृतियों की खोज तथा भारत की आध्यात्मिक राजनय को पुनर्जीवित कर सरकार ने भारत की पहचान में गहरे गौरव की भावना पुनर्जीवित की है। मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में भारत में उल्लेखनीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान देखने को मिला है जिसमें उसकी प्राचीन समृद्ध विरासत के साथ ही आधुनिक राष्ट्र की महत्वाकांक्षायें भी समाहित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस पुनरुत्थान ने भारत की सभ्यतामूलक पहचान को राष्ट्रीय चेतना में अग्रणी स्थान प्रदान किया है तथा सांस्कृतिक बहाली को प्रशासन का एक मुख्य बिंदु बना दिया है। पवित्र मंदिरों तथा तीर्थयात्रा मार्गों को पुनर्जीवित करने और लंबे समय से अनदेखी का शिकार ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को याद करने के सरकारी प्रयासों ने गौरव और एकता की भावना गहराई तक पुनर्जीवित की है।

इस पहल से न केवल भारत की अनादि परंपराओं को संरक्षित करने में सहायता मिली है, बल्कि इसे प्रगति और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की यात्रा से भी जोड़ा गया है। मोदी सरकार में सांस्कृतिक पुनरुत्थान केवल परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक विविधता एवं सांस्कृतिक एकता का उत्सव भी है। नवंबर, 2019 में करतारपुर कॉरीडोर का उद्घाटन इस समावेशी दृष्टिकोण का प्रतीक है जो सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहब की यात्रा की अनुमति देता है। इस पहल ने भाजपा सरकार को सभी विश्वासों और उनकी पवित्र भौगोलिक पहचानों से जुड़ने और गहरे सम्मान का अवसर दिया है।

जनवरी 2024 में अयोध्या में श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। केवल मंदिर का उद्घाटन न होकर यह भारत की दीर्घकालीन सांस्कृतिक प्रतिबद्धता, विश्वास बहाली, पहचान तथा न्यायिक भावना का प्रकटीकरण है। भव्य श्रीराम मंदिर की शानदार उपस्थिति भारत की पुनर्जीवित आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। काशी विश्वनाथ कॉरीडोर भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है जो पवित्र विरासत से पुनर्जीवित संबंध की पुष्टि करता है। पहले यह स्थान संकरी गलियों, भीड़ भरी सड़कों से भरा था जो अब शानदार कॉरीडोर में बदल गया है तथा गंगा के घाटों से पवित्र मंदिर को जोड़ता है। यह परिवर्तन भौतिकता से आगे बढ़ते हुए एक आध्यात्मिक पुनर्जीवन है जिसने वाराणसी को भक्ति के जीवन्त केन्द्र के रूप में विकसित किया है।

उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर को परंपरागत वास्तु तथा आधुनिक ढांचागत संरचना में समन्वय के रूप में स्थापित किया है जो गहन आध्यात्मिक अनुभव कराता है। इसी प्रकार पार्वती मंदिर तथा सोमनाथ कालगातार विस्तार भक्तों की आध्यात्मिक यात्राओं को समृद्ध बनाता है। असम में पवित्र कामाख्या मंदिर की ढांचागत संरचना में व्यापक सुधार सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर एकजुट भारत की भावना मजबूत करती है। भारत राष्ट्र की संस्कृति न केवल मंदिरो और वास्तुकला में प्रतिध्वनित होती है, बल्कि यह संगीत, नृत्य, भाषा और मौखिक कथावाचन में भी अभिव्यक्त होती है। डिजिटल संरक्षण और संस्थागत समर्थन के माध्यम से सरकार ने न केवल अपनी प्रशासनिक नीति निर्धारित की है, बल्कि उसने 'राजधर्म' का उच्च दायित्व भी परिभाषित किया है जिससे देश की आत्मा सुरक्षित होती है।

'प्रसाद' योजना के माध्यम से सरकार ने पूरे भारत में धार्मिक स्थलों का गरिमापूर्ण पुनर्जीवन सुनिश्चित किया है। इस योजना में 1,900 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है जिससे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और दरगाहों को पुनर्जीवित किया गया है। इससे न केवल भारत की प्राचीन विरासत का संरक्षण सुनिश्चित हुआ है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थायें भी मजबूत हुई हैं। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही सामाजिक सामंजस्य को भी बढ़ावा मिला है। भारत की आध्यात्मिक व सभ्यतामूलक राजनय ने विश्व स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। जहां 2013 तक केवल 13 चोरी की गई प्राचीन वस्तुयें प्राप्त की गई थीं, वहीं 2014 के बाद से चोरी की गई 642 मूर्तियां तथा प्राचीन कलाकृतियां भारत वापस लाई गई हैं। इससे विश्व स्तर पर राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान की यह भावना न केवल स्मारकों में दिखती है, बल्कि आम जनता भी इसका बहुत गहराई से अनुभव करती है। नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जा रहा है जो विश्व स्तर पर प्रख्यात प्राचीन ज्ञान का भंडार रही है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की विश्व स्तर पर पहचान तथा गुरु नानक देव जी व गुरु गोविन्द सिंह जी की जन्म जयंतियों पर विश्व स्तर पर अनेक आयोजनों के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत की बौद्धिक व आध्यात्मिक विरासत की भारतीय प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई है। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' तथा 'काशी तमिल संगमम' जैसे कार्यक्रमों से भारत की क्षेत्रीय विविधता पूरी मजबूती के साथ उजागर हुई है।

जब दक्षिण भारत के कलाकार, विद्वान तथा धार्मिक गुरु उत्तर भारत में अपनी संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए एकत्र होते हैं तो इसे भारत की आत्मा प्रसन्न होती है तथा पूरे राष्ट्र की एकजुटता सुनिश्चित होती है। 2025 में काशी तमिल संगमम में दो लाख से अधिक यात्री आए तथा सैकड़ों आयोजन किए गए। यह भारत में सभ्यतामूलक व आध्यात्मिक भावना की जागृति का स्पष्ट प्रमाण है। इसका संबंध केवल उत्सव के आयोजन से नहीं था, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मका का महान उत्सव था जिसने हर जाति, समुदाय, क्षेत्र और विश्वास में सामंजस्यपूर्ण एकजुटता का प्रदर्शन किया है। लंबे समय से भारत की न्याय प्रणाली औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित थी जिनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के बजाय उन पर नियंत्रण करना था।

मोदी सरकार द्वारा 'भारतीय न्याय संहिता' लागू करना केवल कानूनी सुधार न होकर भारत की संप्रभु भावना की शक्तिशाली पुष्टि है। स्वतंत्रता के बाद से अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव तथा वोटबैंक खोने के भय से अनिर्णीत पड़े थे। विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दे, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक की समाप्ति, अनुच्छेद 370 की समाप्ति तथा नागरिकता संशोधन कानून इतने जटिल समझे जाते थे कि राजनेता उनको छूने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इन चुनौतियों से अल्पकालीन राजनीतिक लाभ के बजाय स्पष्टता, प्रतिबद्धता तथा दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को देखते हुए निपटा गया। इस प्रकार पूरे देश के करोड़ों लोगों का विश्वास और आत्मविश्वास बहाल हुआ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल स्मारक बनवा रहे हैं, बल्कि वे भारत की आत्मा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। गुजरात में सरदार पटेल के स्मारक समेत अनेक राष्ट्रनायकों व जननायकों के स्मारकों का निर्माण पिछले सालों में हुआ है जिससे पूरे देश में विरासत के प्रति गर्व के साथ एकजुटता की भावना मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल निर्णायक एवं प्रभावी नेतृत्व के साल रहे हैं जो परंपरागत प्रशान से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय चेतना का नया युग शुरू करते हैं। विकास को विरासत तथा प्रगति को परंपरा से अभिन्न रूप से जोड़ कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की आत्मा पुनर्जीवित की है तथा एक आत्मनिर्भर व विश्वास से भरे राष्ट्र की नीव डाली है।

इस आश्वासन और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ भारत अपनी शक्ति अतीत के आंतरिक और आध्यात्मिक विवेक से प्राप्त कर रहा है। यह भारत के सच्चे पुनरुत्सान का मूल आधार है जिसकी जड़ें गहराई से विरासत में समाहित होने के साथ ही यह दूरगामी व भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई सभ्यता अपनी प्रमुख पहचान से जुड़ती है तो वह न केवल स्वयं को जागरूक करती है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करती है। भारत आज इसी मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की 140 करोड़ जनता इससे ऊर्जान्वित अनुभव कर रही है।

रक्तदान कर जीवन बचाएं

> रक्तदाता गुमनाम नायक हैं जिनकी शांत उदारता दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की धड़कन को बनाए रखती है।

मनोहर अगनानी
(लेखक, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं)

इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम - रक्त दें, आशा दें: साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं - रक्तदान करने के अर्थ को खूबसूरती से व्यक्त करती है। यह एक चिकित्सा कार्य से कहीं अधिक है; यह जीवन का उपहार है, एकजुटता का प्रतीक है, और करुणा की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। रक्तदाता गुमनाम नायक हैं जिनकी शांत उदारता दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की धड़कन को बनाए रखती है। रक्तदान के साथ मेरी अपनी यात्रा बहुत पहले शुरू हुई, जो मेरे पिता की रक्तस्राव विकार से लंबी लड़ाई से गहराई से प्रभावित हुई। उन्हें अपने पूरे जीवन में अनगिनत रक्त आधान की आवश्यकता पड़ी, लेकिन अचानक, जीवन-धमकाने वाले मस्तिष्क रक्तस्राव के दौरान कोई भी उतना जरूरी नहीं था। आपातकालीन सर्जरी ने उन्हें बचाया - लेकिन केवल इसलिए क्योंकि रक्त पहले ही दान किया जा चुका था, संग्रहीत किया जा चुका था, और उपलब्ध कराया जा चुका था।

मैं उन अजनबियों के प्रति कृतज्ञता की लहर को कभी नहीं भूलूंगा जिन्होंने उन्हें जाने बिना रक्त दिया था। रक्त की प्रत्येक इकाई जीवन के जाल में एक धागा थी जिसने उन्हें संकट के दौरान एक साथ रखा। प्रत्येक रक्तदाता - चाहे वह मित्र हो, परिवार का सदस्य हो, या बिल्कुल अजनबी हो - जीवन-रक्षक श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। उनकी निस्वार्थता अथाह है। आधुनिक चिकित्सा के लिए रक्त आधान महत्वपूर्ण है। सर्जरी से गुजरने वाले, आघात या दुर्घटनाओं से जूझ रहे, गंभीर एनीमिया या कैंसर से पीड़ित और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जैसे वंशानुगत रक्त विकारों के प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है। अक्सर, एक ही दान जीवन और मृत्यु के बीच एक पुल बन जाता है। वैश्विक स्तर पर, दो मुख्य दाता श्रेणियां मौजूद हैं- स्वैच्छिक दाता और परिवार/प्रतिस्थापन दाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1997 से स्वैच्छिक, अवैतनिक रक्तदान में बदलाव की जोरदार वकालत की है। इन दानों को सबसे सुरक्षित, सबसे नैतिक और सबसे टिकाऊ माना जाता है। इसके विपरीत, पारिवारिक या प्रतिस्थापन दान - जब कोई व्यक्ति किसी रिश्तेदार या मित्र के लिए विशेष रूप से रक्त दान करता है - अक्सर भावनात्मक दबाव शामिल होता है और कम सुरक्षित होता है। ये ग्राफ्ट बनाम होस्ट रोग जैसे स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकते हैं, जब आनुवंशिक रूप से समान दाता रक्त प्राप्तकर्ता के शरीर पर हमला करता है। सुरक्षित और स्थिर रक्त आपूर्ति के महत्व को पहचानते हुए, भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से रक्त बैंकों को धन, उपकरण, जनशक्ति और संग्रह तथा परिवहन के लिए वाहनों के साथ सहायता प्रदान करता है। सरकार मरीजों को संसाधित रक्त की नि:शुल्क उपलब्धता को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य जेब से होने वाले खर्च को कम करना और स्वैच्छिक दान को प्रोत्साहित करना है। एक उल्लेखनीय पहल ई-रक्तकोष है, जो सी-डैक द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत रक्त बैंक प्रबंधन प्रणाली है। यह 4,300 से अधिक रक्त केंद्रों को जोड़ता है, जिससे रक्त की उपलब्धता, ऑनलाइन दाता पंजीकरण और राष्ट्रव्यापी समन्वय के लिए वास्तविक समय की पहुँच मिलती है। उमंग ई-हॉस्पिटल और आरोग्य सेतु जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत होने से यह दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच में सुधार करता है। नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड कनेक्ट और संकल्प इंडिया फ़ाउंडेशन जैसे संगठनों ने स्वैच्छिक दान का समर्थन करने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाए हैं। 24/7 हेल्पलाइन से लेकर सुव्यवस्थित रक्त शिविरों और आपातकालीन सेवाओं तक, उनके प्रयासों से हर साल हजारों लोगों की जान बचती है। इस प्रगति के बावजूद, भारत अभी भी डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित जनसंख्या के 1 प्रतिशत की दान दर से पीछे है। 2022 में, केवल 0.8 प्रतिशत ने रक्तदान किया, जिसके परिणामस्वरूप सालाना लगभग दस लाख यूनिट की कमी आई। यह अंतर भारत की बढ़ती उम्र की आबादी को देखते हुए विशेष रूप से चिंताजनक है। 2050 तक, 347 मिलियन से अधिक भारतीय 60 वर्ष से अधिक आयु के होंगे - एक ऐसा जनसांख्यिकीय समूह जिसे रक्ताधान की आवश्यकता होने की अधिक संभावना है, फिर भी अक्सर दान करने के लिए अयोग्य होता है। भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए, हमें बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक जागरूकता दोनों को मजबूत करना होगा। एआई जैसी उन्नत तकनीकें डोनर स्क्रीनिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन को अनुकूलित करने में मदद करेंगी, लेकिन स्वैच्छिक मानवीय भागीदारी अपूरणीय बनी हुई है। हमें नागरिकों - विशेष रूप से युवाओं को - आजीवन दाता बनने के लिए शिक्षित, प्रेरित और प्रेरित करना जारी रखना चाहिए। हम लीला मूलगांवकर और सर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी जैसे पिछले अग्रदूतों और किरण शर्मा और सुरेश कुमार सैनी जैसे वर्तमान नायकों से भी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिनके स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति समर्पण ने जीवन बदल दिया है। उनकी विरासत एक अनुस्मारक है- जब हम रक्त देते हैं, तो हम केवल एक तरल पदार्थ दान नहीं करते हैं - हम आशा, उपचार और मानवता प्रदान करते हैं। आइए हम उनकी भावना का सम्मान करें। आइए हम रक्त दें। आइए हम आशा दें। हम सब मिलकर जीवन बचाते हैं।

आप की बात

पाकिस्तान पर शिकंजा

पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर शिकंजा कस सकता है। आंतकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्रसंघ की संस्था फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ ने कहा है कि पहलगाम कश्मीर में हुआ आतंकी हमला टेरर फंडिंग के बगैर सम्भव नहीं है। इससे पाकिस्तान को फिर से आतंक-समर्थकों की ग्रे लिस्ट में डाले जाने का आधार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इस संस्था ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा है कि उसने अब टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए कई देशों की ओर से उठाए गये कदमों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा स्वयं को आतंकवाद का पीड़ित बताना हास्यास्पद लगता है। आपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की नमाजे जनाजा में पाकिस्तान के वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के साथ बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति तथा उनके ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडा लगाने व सैनिकों द्वारा सैल्यूट देने से स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में स्टेट और नान-स्टेट एक्टर्स में कोई अंतर नहीं है। इसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकवाद की फंडिंग स्वत: स्पष्ट हो जाती है। भारत को दुनिया के सभी देशों के साथ मिल कर एफएटीएफ को प्रेरित करना चाहिए कि पाकिस्तान पर फिर इस मामले में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

- **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

उत्तराखंड में पर्यटन

उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, विशेषकर चारधाम यात्रा के दौरान। इस भीड़ को संभालने के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं एक सुविधाजनक विकल्प बनकर उभरी हैं, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी और पर्यावरण पर असर जैसे गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। यात्रा सीजन सीमित होने के कारण अधिक लाभ कमाने की होड़ में कई विमान कंपनियाँ निर्धारित मानकों से समझौता कर रही हैं। अधिक यात्रियों को भरना, पुराने उपकरणों का प्रयोग, उड़ान से पहले समुचित जांच में ढिलाई और पायलटों की थकान को नजरअंदाज करना आम होता जा रहा है। हाल ही में उत्तरकाशी हादसे और सड़क पर हेलिकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग जैसी घटनाएं इस लापरवाही की गवाही देती हैं। इसका एक और गंभीर पहलू पर्यावरणीय प्रभाव है। लगातार उड़ानों से पर्वतीय इलाकों में ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे न केवल जैव विविधता पर असर पड़ रहा हैए बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी भी बिगड़ रही है। ऐसे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और राज्य सरकार को मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड को पड़ोसी देश भूटान की तरह पर्यटकों की संख्या सीमित करने पर भी विचार करना चाहिए।

- **मधु सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

खबरों की दुनिया

रेडियो अब कल की बात हो गई है और खबरों के मामले में टेलीविजन का भी यही हाल हो सकता है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब कई लोगों के लिए खबरों का प्राथमिक स्रोत बन गए हैं और वे पारंपरिक टेलीविजन समाचारों और समाचार वेबसाइटों से आगे निकल गए हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि 54 प्रतिशत अमेरिकी अपनी खबरें सोशल मीडिया से प्राप्त करते हैं, जबकि 50 प्रतिशत टीवी और 48 प्रतिशत वेबसाइट से। यह बदलाव लोगों के समाचारों के उपभोग के तरीके में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है जिसमें फेसबुक, वाट्सएप, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की ओर झुकाव शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार समाचारों का उपभोग विखंडित होता जा रहा है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुँच रहे हैं। यह प्रवृत्ति केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया से गलत सूचनायें व फर्जी खबरें फैलने की संभावना है। खबरों की बदलती दुनिया प्रिंट मीडिया के लिए खासतौर से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक आधिकारिक, तटस्थ व विश्वसनीय खबरें प्रिंट माध्यम से ही मिलती हैं।

-**जंग बहादुर सिंह**, जमशेदपुर

ट्रंप के दावे

ट्रम्प ने एक बार फिर भारत-पाक युद्ध रुकवाने का दावा करते हुए कहा कि मैं इजराइल-ईरान युद्ध रुकवा दूंगा। वे रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका कोई प्रभाव या दबाव काम नहीं आया। भारत-पाक युद्ध तो पाकिस्तान द्वारा भारत के सामने गिड़गिड़ाने से रुका। भारत ने अपनी शर्तों पर ऑप्रेशन सिंदूर स्थगित करने के साथ यह भी कह दिया कि अगर फिर कोई आतंकी घटना हुई तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और सेना जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। ट्रंप के बड़बोले दावे वर्तमान स्थितियों में उनको अविश्वसनीय और हास्यास्पद बना रहे हैं। वे इस्राइली हमले का परोक्ष समर्थन कर ईरान को नाभिकीय संधि के लिए धमका रहे हैं और ज्यादा गंभीर इस्राइली हमले का डर दिखा रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि ट्रंप की दुनिया में दादागीरी के प्रयासों की हवा अमेरिकन जनता और अदालतें ही निकालने में लगी हैं। कहा जाता है कि ट्रंप अमेरिकन बुद्धिजीवियों के बजाय उन लोगों के पक्ष में हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है।

- **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
विवेक ही उचित-अनुचित का भेद बताता है

विमान यात्रियों का संकट

अहमदाबाद में दिल दहलाने और भारत समेत विश्व भर को चिंतित करने वाली विमान दुर्घटना के बाद से एअर इंडिया की उड़ानें जिस तरह तकनीकी खामी, धमकी समेत अन्य कई कारणों से लगातार रद, बाधित या विलंब का शिकार हो रही हैं, वह गंभीर बात है। इसलिए और अधिक, क्योंकि इनमें कुछ उड़ानें बोइंग कंपनी के उस ड्रीमलाइनर विमान की भी हैं, जो अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ और जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए। बीते 24 घंटों में ही एअर इंडिया के विमानों की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें स्थगित या रद हुईं। इसने एअर इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी के साथ हवाई यात्रा करने वालों के समक्ष भी परेशानी बढ़ गई है। इसका सामना विमान यात्रियों के साथ ट्रैवल कंपनियां और टूर आपरेटर भी कर रहे हैं, क्योंकि अन्य एयरलाइंस पर दबाव बढ़ रहा है। इस समस्या पर सरकार के साथ डीजीसीए जैसी नियामक एजेंसियों को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब हवाई यात्रा करना लोगों की जरूरत बन गया है। इसीलिए विमान यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और यह कहा जाने लगा है कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। हवाई यात्रा सुगम और सुरक्षित होनी ही चाहिए।

अहमदाबाद हादसे और उसके बाद ड्रीमलाइनर विमानों वाली उड़ानों के भी रद या स्थगित होने से बोइंग कंपनी के इस विमान के सुरक्षित होने पर संदेह के बादल गहरा गए हैं। ये बादल देश में ही नहीं, विदेश में भी गहराए हैं। एअर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर का उपयोग जारी रखने पर विचार करना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि बोइंग का यह विमान पहले भी विवादों के साये में रह चुका है। भारत में भी उसके इन विमानों की बैटरी में कुछ समस्या पाई गई थी। ड्रीमलाइनर का उपयोग एअर इंडिया के साथ दुनिया भर की अन्य एयरलाइंस भी कर रही हैं। तथ्य यह भी है कि देश-विदेश में अपनी सेवा का तेजी से विस्तार कर रही एअर इंडिया ने ड्रीमलाइनर के कुछ और विमान खरीदने का आर्डर दे रखा है। अन्य एयरलाइंस की तरह उसे भी अपने विस्तार को लेकर महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा में बिना किसी समझौते के। सुविधाओं में कमी की कीमत पर भी नहीं। निःसंदेह सुविधाओं के मुकाबले सुरक्षित विमान यात्रा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी और इसे सरकार को भी देखना होगा, अन्यथा विमान यात्रा के प्रति लोगों के मन में उपजा संदेह और बढ़ेगा। यह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। इससे तेजी से अपना कद बढ़ा रहे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हो सकती है। निःसंदेह केवल इतना पर्याप्त नहीं कि सरकार ने ड्रीमलाइनर 787 सीरीज के सभी विमानों की जांच के आदेश दिए हैं।

ड्रेनेज पर तंत्र की सुस्ती

उत्तराखंड में मानसून ने भले ही अभी दस्तक नहीं दी है, लेकिन प्री-मानसून वर्षा में ही दिक्कतें खड़ी होने लगी हैं। जल जमाव के कारण शहर हांफने लगे हैं। शायद ही ऐसा कोई शहर होगा, जहां लोग इस परेशानी से न जूझ रहे हों। हल्की सी वर्षा में मुख्य मार्ग, संपर्क मार्ग और बाजार तालाब बन जा रहे हैं। आवासीय कालोनियों की भी यही स्थिति है। अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण परेशानी बढ़ा रहा है। समस्या पुरानी है, पर समाधान के लिए कभी प्रभावी पहल होती नहीं दिखी। प्री-मानसून में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, वह स्थानीय निकायों की मानसून तैयारियों के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। नालों की सफाई का ढोल पीटा गया, पर वर्षा वाले दिन असलियत सामने आ रही है। दो राय नहीं कि पिछले ढाई दशक में शहरों में जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ा है और उसी गति से शहरीकरण भी हुआ। बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स, शापिंग माल और अन्य प्रतिष्ठान खड़े हुए हैं, पर इनमें भी जल जमाव से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। तंत्र की लापरवाही की इंतहा यह कि उसने ड्रेनेज प्लान तक ठीक से नहीं बनाया। बातें खूब हुईं, आंकड़ेबाजी भी खूब चली, प्रस्ताव बने, लेकिन फाइलों में ही कैद होकर रह गए। यही कारण है कि जरा सी वर्षा शहर पर आफत बनकर टूट पड़ती है। चिंता की बात यह कि जिम्मेदारों को इसका अहसास ही नहीं है। जनप्रतिनिधियों का भी इससे सरोकार नहीं दिखता। जल जमाव प्रभावित क्षेत्रों में समर्थकों संग फोटो खिंचवाकर मीडिया की सुर्खियां बनने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी दिखती है। इस प्रवृत्ति से बाहर निकलने की जरूरत है।

> तंत्र की सुस्ती सवाल खड़े कर रही है कि ड्रेनेज को लेकर क्या शहरवासियों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं?

आर्थिक रूप से और सक्षम बनने का समय

जीएन वाजपेयी

कुछ देश अपने आर्थिक रुतबे को ही ताकत बनाकर न केवल पड़ोसियों, बल्कि दुनिया भर को धौंस दिखाते हैं। भारत भी अपना आर्थिक कद ऊंचा करने के प्रयासों को गति दे

आपरेशन सिंदूर की सफलता का अलग-अलग पहलुओं से विश्लेषण जारी है। इस सैन्य अभियान की सफलता ने मुख्य रूप से तीन सराहनीय पहलुओं को रेखांकित करने का काम किया। पहला भारत सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, जिसने पहलगाम में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण, बर्बर और शर्मनाक कृत्य के जवाब में एक अपेक्षित एवं प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित किया। दूसरा, स्वदेश विकसित एवं निर्मित हथियार प्रणालियों की सफलता और हमारे सशस्त्र बलों का अद्वितीय साहस। तीसरा, देश के सभी वर्गों, जाति, पंथ के लोगों ने राजनीतिक विचारधारा से परे जाकर हमारे सैनिकों की वीरता के समर्थन और प्रशंसा में एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस सफलता में गर्व की अनुभूति और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि स्वदेश निर्मित रक्षा प्रणालियों ने अपनी उपयोगिता साबित की। इसने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की गति को और तेजी देने की आवश्यकता को दर्शाया है। इसके लिए हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनना होगा। यहां यह न भूला जाए कि कुछ देश अपने आर्थिक रुतबे को ही ताकत बनाकर न केवल पड़ोसियों, बल्कि दुनिया भर को धौंस दिखाने का काम करते हैं। यहां तक कि वे नैरेटिव पर भी नियंत्रण रखते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का एलान किया है। निःसंदेह राजनीतिक संकल्पशक्ति और हमारे सैन्य बलों का पराक्रम तात्कालिक रूप से इस चुनौती से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन इसका दीर्घकालिक उपाय आर्थिक मजबूती से ही जुड़ा है कि हमें परेशान करने की मंशा रखने वालों के मन में यह भय व्याप्त हो कि भारत पर बुरी नजर डालने के नतीजे कितने भयावह होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो एक राष्ट्रीय स्वप्न परवान चढ़ा है, उसके साकार होने पर ऐसी निवारक शक्ति सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हालांकि इस सपने की पूर्ति के लिए देश को निरंतर आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। ऐसी ऊंची वृद्धि कम से कम 36 प्रतिशत के सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के जरिये ही प्राप्त की जा सकती है। यह तभी संभव है, जब बचत और निवेश दर कुल आर्थिक उत्पादन के 36 प्रतिशत से अधिक हो। अफसोस की बात यह है कि जीसीएफ लगातार घटने पर है। वित्त वर्ष 2024 में यह और घटकर 31.4 प्रतिशत हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में यह 32.8 प्रतिशत था। इसका

अवधेश राजपूत

मुख्य कारण निजी क्षेत्र के निवेश में कमी आना है। निजी क्षेत्र का निवेश भी वित्त वर्ष 2023 के 25.8 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 24 प्रतिशत ही रह गया। इस दौरान रिकार्ड सरकारी निवेश हुआ, लेकिन वह इस मोर्चे पर कमी को पूरा करने के लिहाज से पर्याप्त नहीं।

जीडीपी वृद्धि दर को गति देने के दो रास्ते हैं। एक निवेश यानी आपूर्ति केंद्रित और दूसरा मांग यानी उपभोग केंद्रित। जहां चीन ने निवेश केंद्रित राह अपनाई तो भारत ने उपभोग आधारित विकल्प की ओर कदम बढ़ाए। सुसंगत आर्थिक वृद्धि तभी सुनिश्चित होती है जब आपूर्ति (निवेश) और मांग (उपभोग) में समन्वय स्थापित हो सके। निवेश आधारित माडल रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है, जिससे आय बढ़ती है और अंततः उपभोग बढ़ता है। जबकि मांग आधारित वृद्धि में मांग सृजन के लिए लगने वाली अवधि विलोपित हो जाती है और निवेशक को अपनी पूंजी निवेश पर कहीं अधिक तेजी से प्रतिफल प्राप्त होता है। मांग आधारित वृद्धि में निवेश तब गति पकड़ता है, जब क्षमता उपयोग 75 प्रतिशत के स्तर को छू लेता है। रिजर्व बैंक के अनुसार विनिर्माण क्षमता उपयोग का स्तर 76.7 प्रतिशत पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी निजी निवेश अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। कंपनियों के बहीखातों के संतुलन और पूंजी की लागत में बड़ी गिरावट जैसे पहलू भी चुनौती बने हुए हैं। संभव है कि वैश्विक अनिश्चितताएं निजी क्षेत्र के निवेश को लेकर अनिश्चितताएं पैदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदर्भ में कुछ समय पहले हौसला बढ़ाने का भी काम किया। उन्होंने कहा था कि हालिया वैश्विक घटनाक्रम भारत के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ा रही है तो कारोबारी दिग्गज भी जोखिम की परवाह न करते हुए निवेश बढ़ाएं।

भारत जैसे निम्न मध्यम-आय वाली आर्थिकी में विवेकाधीन खर्च करने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। जब तक आमदनी में भारी बढ़ोतरी नहीं होती, तब तक उपभोग या खपत के स्तर पर बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ पाएगी। चीन ने निवेश केंद्रित राह चुनी और उसकी अर्थव्यवस्था ने करीब 40 से भी कम वर्षों में अप्रत्याशित ऊंचाई को छुआ। यह सही समय है कि अंबानी, अदाणी, टाटा, बिड़ला, डालमिया और इन जैसे अन्य कारोबारी घराने एवं उद्यमी मांग में तेजी आने और वैश्विक अनिश्चितताओं के बादल छंटने का इंतजार करने के बजाय अपना दृष्टिकोण बदलें। वे निवेश की राह पर आगे बढ़ते हुए देश का आर्थिक रुतबा बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सैन्य बल सदैव अपने योगदान के लिए तत्पर रहते हैं और सर्वोच्च बलिदान से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि आर्थिक निवारक शक्ति का विकास उनके लिए कितना मददगार होगा।

भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से यह सिलसिला इसी प्रकार से कायम है और मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल का भारत की वृद्धि पर बहुत ज्यादा असर पड़ने के आसार भी नहीं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि कम से कम अगले एक दशक तक भारत बहुत तेज गति से वृद्धि करेगा। इसलिए निवेश पर प्रतिफल शायद तत्काल बहुत ज्यादा न दिखे, लेकिन दीर्घकाल में यह बहुत व्यापकता एवं समग्रता लिए होगा। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रयास करना भी सच्ची देशभक्ति होगी।

(लेखक सेबी एवं एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)
response@jagran.com

सुनिश्चित की जाए सुरक्षित हवाई यात्रा

राजीव सचान

अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद उत्तराखंड में एक और हेलीकाप्टर हादसे ने चिंता बढ़ा दी है

दुनिया को स्तब्ध और भारतीयों को गहरी पीड़ा से भर देने वाली अहमदाबाद विमान दुर्घटना की चर्चा जारी रहना स्वाभाविक है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि हाल के इतिहास में ऐसा हवाई हादसा याद करना कठिन है, जिसमें इतने अधिक भारतीयों की मौत हुई हो। एअर इंडिया के अभागे 787 ड्रीमलाइनर विमान के उड़ान भरते ही गिरने से एक यात्री के चमत्कारिक ढंग से बच जाने के अतिरिक्त सभी यात्री और चालक दल के सदस्य काल के गाल में समा गए। यह विमान पास के मेडिकल कालेज के जिस हास्टल की कैंटीन पर आग का गोला बनकर गिरा, वहां कुछ मेडिकल छात्र और अन्य लोग भी मारे गए। अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों को लेकर आम लोगों के साथ विशेषज्ञों के अपने-अपने विचार हैं। इनमें एक कैप्टन स्टीव भी हैं, जिन्होंने अहमदाबाद हादसे के कारणों को लेकर जो दावा किया, उसे खुद ही बदल दिया, लेकिन इसके पहले उन्हें एक भारतीय टीवी चैनल पर 'ज्ञान' देते देखा गया। अन्य विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि बोइंग का अपेक्षाकृत नया और आधुनिक ड्रीमलाइनर विमान किन कारणों से ऐसे भयावह हादसे का शिकार बना। चूंकि बोइंग के इस विमान के साथ पेश आया यह पहला बड़ा हादसा है, इसलिए भारत समेत विश्व भर की एयरलाइंस एवं हवाई संचालन सेवा से जुड़ी संस्थाएं चिंतित हैं। इस हादसे की राष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहन जांच हो रही है। इसी के साथ जो प्रश्न उठे हैं, उनके घेरे में एअर इंडिया प्रबंधन, टाटा समूह, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथारिटी और भारत सरकार आदि के साथ बोइंग कंपनी भी है। इस हादसे के बाद बोइंग के अलावा एअर इंडिया में भागीदार सिंगापुर एयरलाइंस (एसआइए) के साथ कुछ अन्य एयरलाइंस के शेयर भी गिरे। अहमदाबाद में हवाई हादसे के बाद से भारत समेत दुनिया भर में विमानों के संचालन में छोटी-बड़ी खामी मिलने, उड़ान रद होने, रोके जाने के समाचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनमें ड्रीमलाइनर समेत अन्य विमान भी हैं।

निर्माण के दौरान अपने विमानों के सेफ्टी सिस्टम की अनदेखी के कारण बोइंग गंभीर सवालों के घेरे में रही है। इस कंपनी के 'व्हिसिलब्लोअर' इंजीनियर सैम ने ड्रीमलाइनर एवं अन्य विमानों के निर्माण में जानबूझकर लापरवाही बरतने का आरोप मढ़ा था। इसके चलते बोइंग की खूब बदनामी हुई थी। बोइंग ने इस इंजीनियर के आरोप खारिज करते हुए कहा था कि वह अपने सभी विमानों के निर्माण में जरूरी सावधानी बरतती है, पर शायद उसने ऐसा नहीं किया। 2021 में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी थी। बोइंग के बदनाम हुए मैक्स विमान इस्तेमाल कर रही इंडोनेशिया और इथोपिया एयरलाइंस के नए विमान 2017-18 में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इन हवाई हादसों की जांच में यह सामने आया था कि मैक्स विमानों के साफ्टवेयर में खामी थी और इस खामी को दूर करने वाले उपायों से विमान के लैस होने का बोइंग ने जो वादा किया था, वह उनमें थे ही नहीं। इसके चलते बोइंग की साख को धक्का तो लगा ही, उस हादसे में मारे गए लोगों के स्वजनों को अदालत के बाहर समझौता करने के बाद भी भारी हर्जाना देना पड़ा। इससे उसे तगड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

अहमदाबाद का न भूलने वाला भयावह विमान हादसा। प्रेट्र

टाटा एयरलाइंस की स्थापना भारत में सिविल एविएशन के जनक जेआरडी टाटा ने की थी। बाद में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और नाम कर दिया एअर इंडिया। एअर इंडिया को कुप्रबंधन और घाटे से उबारने के लिए मोदी सरकार ने उसे निजी कंपनी को बेचने का फैसला लिया। स्वाभाविक रूप से पहली पसंद टाटा समूह बना। 2022 में एअर इंडिया उसके हाथों में चली गई। नाम एअर इंडिया ही रहा। इससे दुनिया में कुछ लोग इसे भारत सरकार की एयरलाइंस समझते हों तो हैरानी नहीं। टाटा समूह के हाथ में जाने के बाद माना यह गया कि अब इसका संचालन सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगा, लेकिन अहमदाबाद का हादसा संकेत कर रहा है कि संभवतः ऐसा नहीं हो सका है। उस पर विमान संचालन में पर्याप्त सजगता न बरतने के आरोप में जुर्माना भी लग चुका है। उसे सुविधाओं में कमी के आरोप से भी दो-चार होना पड़ा है। अहमदाबाद हादसे पर एअर इंडिया प्रबंधन के साथ टाटा समूह स्वाभाविक रूप से दुखी और गंभीर है, लेकिन एअर इंडिया में भागीदार सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में कुछ कहना कठिन है। एसआइए में सिंगापुर सरकार की भी हिस्सेदारी है। वहां के पीएम ने तो अहमदाबाद हादसे पर दुख जताया, पर एसआइए के एक्स(ट्विटर) हैंडल पर संवेदना का एक शब्द नहीं दिखा। अहमदाबाद हादसे को लेकर जो सवाल उठे हैं, उनका उसे भी जवाब देना होगा।

निःसंदेह समय के साथ विमान यात्रा सुरक्षित हुई है, लेकिन हर हवाई हादसे पर विमानों के सुरक्षित संचालन पर वैसे ही सवाल भी उठते हैं, जैसे इन दिनों उठ रहे हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद उत्तराखंड में एक और जानलेवा हेलीकाप्टर हादसे के चलते ये सवाल और अधिक चिंता का कारण बन गए हैं। अब अपने देश में विमान और हेलीकाप्टर सेवाओं का उपयोग बड़ी संख्या में आम आदमी कहे जाने वाले लोग भी करते हैं, क्योंकि हवाई यात्रा जरूरत बन गई है। हवाई यात्रा सुरक्षित हो, यह एयरलाइंस और नियामक संस्थाओं के साथ भारत सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

कल्याण की कामना

आकाश तो एक है, किंतु उसे देखने की दृष्टि सबकी अलग-अलग है। यह दृष्टि दर्शन से उत्पन्न होती है। दार्शनिक के दर्शन और दृष्टिकोण को लिपिबद्ध इसलिए किया जाता है, ताकि अन्य जनों का भी जागरण हो सके। आश्चर्य होता है कि श्मशान और मनुष्य को देखकर क्या हमने कोरोना से लेकर हाल की अहमदाबाद हवाई दुर्घटना और हास्टल में बैठे तेजस्वी लोगों की गति से कुछ नहीं सीखा? अभी भी लोग कोरोना के नाम पर प्रश्नों की झड़ी लगाते रहते हैं। आपने वैक्सीन ली या नहीं ली और यदि एक बार ली तो अन्य क्या उपाय किए? इसके पीछे कहीं न कहीं आपकी पूंजी में सेंध लगाने की मंशा होती है।

इस समय अनेक देश भी एक दूसरे को मारकर किसी काल्पनिक कब्रिस्तान या श्मशान पर राज्य करने की मिथ्या कल्पना में डूबे हुए हैं? प्लास्टिक की बोरियों में जले शरीर गाड़ी की डिक्की में जा रहे हैं। हम किसके लिए यह सब कर रहे हैं? इसका एक ही उत्तर है-अहंकार तथा लोभ का अतिक्रमण। जो जहां है उससे आगे देख रहा है। जबकि बीता हुआ रास्ता भी वही है, जिसकी हमने कभी आकांक्षा की थी। दुख की परिस्थितियां हमने स्वयं निर्मित की होती हैं। हमारा पुनर्जन्म क्या-कहां-कैसे होगा, यह पता नहीं, परंतु लगता है कि हम किसी भी योनि में जाएं, वहां से देखकर यही निर्णय करेंगे कि-हे ईश्वर हमें चाहे जो बनाओ मगर मनुष्य न बनाना।

वस्तुतः, हमारे लिए यही उचित होगा कि हम ईश्वर की अनंत महिमा पर प्रश्नचिह्न न लगाएं। हम ईश्वर का निर्माण न करें। न ही किसी कागज पर लिखी काली स्याही के अक्षरों का उद्धरण दें। उसे काला तो हमने ही बनाया, जबकि वे तो स्वर्णिम अक्षर थे। हमारे लोभ और अहंकार ने ही उनकी विपरीत व्याख्या कर दी। वास्तविक सुख और शांति का एकमात्र मार्ग यही है कि हम इस सृष्टि में सभी के कल्याण की कामना करें।

स्वामी मैथिलीशरण

दुनिया का पहला 'गार्डन स्टेडियम'

सुधीर कुमार

> सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बन रहे दुनिया के पहले हरित स्टेडियम के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है

सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 32 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहे दुनिया के पहले 'गार्डन स्टेडियम' (हरित स्टेडियम) के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह एक ऊर्जा दक्ष, कम कार्बन उत्सर्जक, पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर स्टेडियम होगा, जिसे हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। यह पहली बार है जब कोई स्टेडियम खेल और मनोरंजन का केंद्र होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता प्रसार का भी काम करेगा।

स्पेनिश स्टूडियो फेनविक इरिबारन आर्किटेक्ट्स के द्वारा इस हरित स्टेडियम को बेलग्रेड के बाहरी इलाके सुरसीन में बनाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हरियाली के केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। इस गोलाकार स्टेडियम में चार छल्ले (रिंग) होंगे और हर छल्ले के बीच जो हरित क्षेत्र होगा, वे वर्टिकल गार्डन, वृक्षों की पंक्तियां और छायादार वनस्पति से युक्त होंगे। इस तरह यह एक प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करेगा। स्टेडियम की दुनिया में यह एक अभिनव प्रयोग है, जहां स्टेडियम के निर्माण में प्रकृति को भी समान महत्व दिया जा रहा है। आमतौर पर स्टेडियम कंक्रीट और इस्पात की बुनियाद पर खड़ा होता है और उसमें पर्यावरणीय मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

हरित आवरण होने के कारण यह दर्शकों को प्राकृतिक शीतलन प्रदान करने में सक्षम होगा, जिससे ऊर्जा खर्च के साथ-साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। यह इसलिए भी खास है कि अन्य स्टेडियम जहां अपनी संरचना और गतिविधियों से स्थानीय तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं, वहीं यह स्टेडियम तापमान को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। दिलचस्प यह है कि मूल रूप से फुटबाल स्टेडियम होने के बावजूद यहां अन्य खेल भी खेले जा सकते हैं। यह केवल एक खेल परिसर ही नहीं होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए सांस्कृतिक, अवकाश और सामुदायिक कार्यक्रमों का केंद्र भी बनेगा। यह स्टेडियम आम नागरिकों के लिए सालोंभर खुला रहेगा, जबकि आमतौर पर स्टेडियम विशिष्ट अवसरों पर ही खोले जाते हैं। हरियाली से घिरा यह स्टेडियम कार्बन फुटप्रिंट में कमी, जलवायु परिवर्तन में भूमिका के न्यूनीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। बढ़ती आबादी और ऊर्जा आवश्यकताओं तथा जलवायु परिवर्तन के समानांतर खेल-आयोजनों के पर्यावरणीय नुकसानों को देखते हुए स्टेडियम को इको-फ्रेंडली बनाना खुशहाल भविष्य में अहम योगदान दे सकता है। इससे न सिर्फ धरा की मुस्कान बरकरार रहेगी, अपितु खेल प्रेमियों के साथ-साथ आम नागरिक भी स्वच्छ व शुद्ध पर्यावरण का हकदार बन सकते हैं।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

समय के अनुकूल नीति

'नरमी का हकदार नहीं होता शत्रु' शीर्षक से लिखे आलेख में सुशील पंडित ने आपरेशन सिंदूर का स्थगन तथा इजरायल द्वारा अपना अभियान जारी रखने का तुलनात्मक विश्लेषण तथ्यात्मक रूप से किया है। उन्होंने इस पक्ष में अनेक तर्क दिए हैं कि आपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक पड़ाव तक पहुंचाने से पहले उसे स्थगित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जैसा शत्रु किसी नरमी का हकदार नहीं होता। इसके लिए उन्होंने पूर्व में हुए संघर्षों का भी सटीक उदाहरण दिया कि पाकिस्तान कभी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आया। लेखक के तमाम तर्क उचित हैं, लेकिन यह भी एक पक्ष है कि समय के साथ-साथ हमें अपनी रणनीति भी बदलनी चाहिए। जो नीति पूर्व के युद्धों में ठीक हो सकती थी, वह आज भी प्रासंगिक हो यह आवश्यक नहीं। रूस जैसा शक्तिशाली और अजेय समझा जाने वाला साधनसंपन्न देश भी अभी तक यूक्रेन को लेकर अपने सभी लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाया है। पश्चिम एशियाई क्षेत्र तो ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। इसके उलट भारत को देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत आर्थिक तथा सामरिक रूप से भी विश्व की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यह भी एक कारण है कि उसके लिए किसी अंतहीन सैन्य संघर्ष में उलझे रहने में कोई समझदारी नहीं थी। वहीं, आतंक से निपटने को लेकर नई नीति अपनाकर भी भारत ने यही संदेश दिया कि उसकी ओर आंख उठाने की दुश्मन को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह समय के अनुकूल सही नीति है।

विपिन गोयल, हापुड़

अहिंसा और आत्मरक्षा

अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ जीवनशैली कहा जा सकता है, परंतु राष्ट्र, धर्म, समाज, परिवार या स्वयं के अस्तित्व पर संकट होने पर हिंसा का सहारा लेना कदापि अनुचित नहीं है। रूस को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने पर आमादा था। माना जाता है कि नाटो का सदस्य बन जाने पर नाटो संगठन के अन्य 31 देश वहां पर हथियारों का जखीरा जमा कर देते, जिससे रूस के लिए हमेशा खतरे की घंटी बजती रहती। उस आसन्न खतरे को देखते हुए, आत्मरक्षा हेतु रूस ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। हमास द्वारा सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमले के पश्चात इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर भीषण हमला करके हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने को भी गलत नहीं कहा जा सकता। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 हिंदुओं की नृशंस हत्या के पश्चात भारतीय सेना द्वारा आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए छह मई की रात को पाकिस्तान पर किए गए आक्रमण को भी उचित ही कहा जाएगा।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

शत्रु से नरमी नहीं

सुशील पंडित का आलेख 'नरमी का हकदार नहीं होता शत्रु' अत्यंत सटीक है। पाकिस्तान और चीन तो नरमी के हकदार बिल्कुल नहीं हैं। भारत ने 1947 से ही पाकिस्तान और चीन के प्रति नरमी दिखाई है, जिसका परिणाम 1962 के युद्ध का परिणाम है। नेहरू पाकिस्तान के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम थे, जिसकी परिणति 1948 में आजाद कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र खोने में हुई। 1965 और 1971 में भी बहुत सा जीता हुआ क्षेत्र वापस दे दिया गया। अभी हाल के आपरेशन सिंदूर में भी संघर्ष विराम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया गया। आपरेशन 48 घंटे भी और चलता तो पाकिस्तान और कांग्रेस एवं विपक्ष के कुछ नेता झूठा नैरेटिव चलाने लायक ही न बचते। भारत को इजरायल से सीखना चाहिए और निर्णायक चोट पहुंचानी चाहिए। वैसे हमने 100 घंटे से भी कम समय में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। सबसे बड़ी चोट है, सिंधु जल समझौता रद करना। इससे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है, और वह अनेक देशों से समझौते की गुहार लगा रहा है। संक्षेप में, भारत को पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के साथ हमेशा सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसे ही चीन भी किसी नरमी के लायक नहीं है।

सीपी बंसल, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

146.39 करोड़ तक पहुंच गई है भारत की जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र की नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार।

डा. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन

आजकल

भारत की दशा-दिशा बताएगी जनगणना

भारत की जनगणना कराने की आधिकारिक घोषणा हो गई है। इसका सबको इंतजार था। अब दो चरणों में होने जा रही इस जनगणना के परिणामों से न केवल देश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आएगा, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नई संभावनाएं और चुनौतियां भी प्रस्तुत करेगा। यह देश की जनसंख्या नीति को लेकर एक नया सोच और दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इससे भारत को अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने और एक सर्वसमावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी

शुरू हुई विश्व की सबसे बड़ी आबादी की विशिष्टताओं को जानने की कवायद। प्रतीकात्मक

केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरे चरण में, प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारियां एकत्र की जाएंगी। जाति जनगणना, जो लंबे समय से राजनीतिक विवाद का विषय रही है, इस बार पहली बार आजाद भारत में होगी। इस कार्य के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है। वैसे तो जनगणना हर 10 वर्षों में होती है, मगर इस बार इसमें डेढ़ दशक लग गए। कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। इसके पहले साल 2011 में जनगणना हुई थी। इससे जनसंख्या के आकार, लिंग और उसकी आयु के अनुसार उसकी जटिल संरचना का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर लोगों की आमदनी में हुई वृद्धि, आबादी के अनुपात में खाद्य पदार्थों एवं पेयजल, आवास, परिवहन, संचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं सुरक्षा की स्थिति की भी जानकारी मिलती है। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में ही लोकसभा और विधानसभा सीटों को परिसीमन के जरिए बढ़ाया जाता है।

इस बार जनगणना के लिए मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा और डिजिटल माध्यमों के साथ-साथ लोगों को स्व-गणना का प्रविधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित की गई तिथि के अनुसार इसका पहला चरण एक अक्टूबर, 2026 तक, जबकि दूसरा और अंतिम चरण एक मार्च, 2027 तक पूरा होगा। समय के लिहाज से देखें तो पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। एक मार्च, 2027 की आधी रात तक देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा, वही रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे।

इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू होगा, जिससे देश में एक नई राजनीतिक चर्चा का आरंभ होगा। दक्षिण भारत के राज्य पहले ही विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या में कमी के डर से चिंतित हैं। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए 2023 में जो महिला आरक्षण अधिनियम बना था, उसे भी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना है। इसके लिए भी यह जनगणना आधार बनेगी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा में एक नई तस्वीर उभरने की संभावना है। जाति जनगणना का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जाति की गिनती से शिक्षा और नौकरियों में ज्यादा आरक्षण की बात होगी। जाति जनगणना के चलते सियासी फलक पर इस बार की जनगणना को एक नए नजरिये से देखा जा रहा है।

भारत की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी, जो 2001 तक एक अरब को पार कर गई और 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा 121 करोड़ का हो गया। संयुक्त राष्ट्र की नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन को अपनाया। इसके बावजूद आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। भारत में जनसंख्या विस्फोट समावेशी विकास के लिए एक चुनौती है। देश में जनसंख्या नीति को लेकर कवायद आजादी के बाद ही शुरू हो गई थी, पर तब इसे समस्या नहीं मानने के कारण इसे तवज्जो नहीं दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या वृद्धि में तेजी महसूस की गई। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति सरकार की प्राथमिकता में आई। इसके बाद पांचवीं योजना में आपातकाल के दौरान 16 अप्रैल, 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को अनिवार्य नसबंदी का कानून बनाने का अधिकार मिला, लेकिन सरकार के पतन के साथ यह नीति भी छिन्न-भिन्न हो गई। 1977 में केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार आने पर एक बार फिर नई जनसंख्या नीति पर विचार किया गया। उसने पुरानी नीति से सीख लेते हुए अनिवार्य नसबंदी को समाप्त कर स्वेच्छा के सिद्धांत को महत्व दिया। इस नीति का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर जून 1981 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में संशोधन हुआ, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जारी रही। चीन में 1979 में प्रारंभ हुई एक बच्चा नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 तक चीन में जन्म दर 2.81 प्रतिशत से आज घटकर 1.51 प्रतिशत हो गई है। इसके कारण वहां युवाओं की संख्या में कमी और बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए भारत में कई विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की तत्काल आवश्यकता नहीं है। फिर भी दो बच्चा नीति पर चर्चा जारी है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। भारत को अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यह न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि देश की स्थिरता और समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। देश में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में नई जनगणना एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकती है।

इस जनगणना के परिणामों से न केवल राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आएगा, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नई संभावनाएं और चुनौतियां भी प्रस्तुत करेगा। जनसंख्या नीति को लेकर एक नई सोच और दृष्टिकोण की जरूरत है, ताकि भारत अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सके और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके।

जनगणना के लिए दस वर्ष का इंतजार क्यों

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

आज तेज भागती जिंदगी में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार एवं संरचना की जानकारी हासिल करने के लिए दस साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज में जिस तेजी से लैंगिक, रोजगारमूलक और जीवन स्तर में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम जनगणना की परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन लाएं। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंपी जाए। गिनती के विकेंद्रीकरण का यह नवाचार जहां 10 वर्षीय जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश को प्रतिमाह जन से संबंधित सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे। इसके लिए न भारी-भरकम संस्थागत ढांचे की जरूरत है और न ही सरकारी अमले की। केवल गिनती की केंद्रीयकृत जटिल पद्धति को विकेंद्रीकृत करके सरल करना होगा। गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरू न होकर नीचे से शुरू होगी। देश की सबसे छोटी राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है, जिसका त्रिस्तरीय ढांचा विकास खंड एवं जिला स्तर तक है। एक जनगणना संबंधी पंजी पंचायत कार्यालय में रखी जाए। उस पंचायत में हर माह जनगणना संबंधी जो भी बदलाव या नई जानकारी आए उसे इस पंजी में दर्ज की जाए। इन सभी आंकड़ों को सीधे कंप्यूटर में फीड किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को जनगणना संबंधी वेबसाइट से जोड़कर इन आंकड़ों का पंजीयन सीधे अखिल भारतीय स्तर पर हो सकता है।

परिवार को इकाई मानकर सरपंच, सचिव और पटवारी को यह जवाबदेही सौंपी जाए कि वे परिवार के प्रत्येक सदस्य का नामकरण एवं अन्य जानकारियां जनसंख्या प्रारूप के अनुसार जगनणना पंजी में दर्ज करें। इस गिनती को सचित्र भी किया जा सकता है। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को बखूबी जानता है इसलिए इस गिनती में चित्र एवं नाम के स्तर पर भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं होगी। जैसे कि मतदाता सूचियों और मतदाता परिचय-पत्र में हो जाती है। गिनती की इस प्रक्रिया से कोई वंचित भी नहीं रहेगा, क्योंकि जनगणना किए जाने वाले जन और जनगणना करने वाले लोग स्थानीय होंगे। गांव में किसी भी शिशु के पैदा होने की जानकारी और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी तुरंत पूरे गांव में फैल जाती है। परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव के बारे में भी सबको पता चल जाता है। अतः इस जानकारी को अविलंब पंजी में दर्ज किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत पर एकत्रित होने वाली यह जानकारी प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख को विकासखंड स्तर पर पहुंचाई जाए। फिर जिले के सभी विकास खंडों की यह जानकारी जिला स्तर पर भेजी जाए। इस तरह से सभी विकासखंडों के आंकड़ों की गणना कर जिले की जनगणना प्रत्येक माह होती रहेगी। जिलेवार गणना के डाटा को प्रदेश स्तर पर सांख्यिकी कार्यालय में इकट्ठा कर प्रदेश की जनगणना का आंकड़ा भी प्रत्येक माह सामने आता रहेगा। प्रदेशवार जनसंख्या के आंकड़ों को देश की राजधानी में जनसंख्या कार्यालय में संग्रहीत कर प्रत्येक माह देश की जनगणना का वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक आंकड़ा मिलता रहेगा। देश के नगर एवं महानगर वार्डों में विभक्त हैं। अतः वार्डवार जनगणना के लिए गिनती की उपरोक्त प्रणाली ही अपनाई जाए। इस गिनती में जितनी पारदर्शिता और शुद्धता रहेगी, उतनी किसी अन्य पद्धति से संभव नहीं है।

खरी-खरी

वैचारिक प्रतिबद्धता

डा. प्रदीप मिश्र

नेताजी ने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। पार्टी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया तो उनके विचार ने कहा, 'यह मेरा तिरस्कार है। यह गरीब-गुरबों का अपमान है। छोड़ तू यह पार्टी, यही तेरे विचार का विचार है।' नेताजी ने विचार को राजनीतिक आधार दिया, 'पार्टी ईमानदारी और सदाचार के विचारों से दूर हो चुकी है। ऐसे में मेरे जैसे विचारशील विचारकों का इससे जुड़ा रहना संभव नहीं है। मैं इसी वक्त पार्टी छोड़ रहा हूं।' फिर उनके विचार एक दूसरी पार्टी के विचारों से मेल खाने लगे, लेकिन उस पार्टी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। ऐसे में उनके विचारों का निरादर होना स्वाभाविक था। और वह पार्टी से अलग हो गए। कहा, 'पार्टी ने विचारहीनता के कारण उनके विचारक बेटे को टिकट नहीं दिया।' फिर वह उस पार्टी में शामिल हुए, जिससे उनके विचार फिलवक्त मिल रहे थे। मतलब उनके बेटे को टिकट मिल रहा था।

एक बार भू-माफिया डान कुमार से वर्षों से चला आ रहे उनके वैचारिक मतैक्य में भिन्नता आ गई। डान लोगों को मारने का काम करता था और नेताजी डान को बचाने का काम करते थे। मारने वाले से बड़ा, बचाने वाला होता है। ऐसे में उसका हिस्सा भी ज्यादा होना चाहिए। इधर कुछ दिनों से डान, धरा-तल पर बिखरी जमीनों की खरीद-फरोख्त करने लगा था। यह आर्थिक ही नहीं, वैचारिक-कृतघ्नता भी थी? अब डान कुमार नेता-द्रोह का दंड भोगते हुए जेल में कैद है और नेताजी का वैचारिक-रक्त उनका पुत्र, भू-माफिया के दायित्व का निर्वहन कर रहा है।

नेताजी के विचार उनकी धर्मपत्नी से भी मेल नहीं खा रहे थे। तलाक देकर उन्होंने संबंधों की वैचारिकी को तिलांजलि दे दी। फिर उनके विचार कम उम्र की एक अबला से मिलने लगे। दोनों के विचारों में अद्भुत सामंजस्य था। फिर एक दिन तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर उसने उनके विचारों का बाजा बजा दिया। भाग्यशाली थे जो हनीमून से सही सलामत वापस आ गए। अब उन्हें ऐसे किसी साथी की तलाश है जिससे उनके विचार, आचार की तरह संरक्षित हो सकें।

विचारों के प्रति नेताजी की प्रतिबद्धता अनुकरणीय है।

पोस्ट

यह स्वागतयोग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्किये के अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। हमें साइप्रस की संप्रभुता के समर्थन में खड़े रहना चाहिए।
अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

कुछ लोग यह राग अलाप रहे है कि तीसरा विश्व युद्ध अब छिड़ा और तब छिड़ा। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ऐसे लोगो को लगता है कि यह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि स्टार वार्स सीरीज की कोई फिल्म हो, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी।
सुशांत सरीन@sushantsareen

उड़ान के दौरान मुझे कुछ घबराहट महसूस होती है। मेरे जैसे और तमाम लोग होंगे। एअर इंडिया विमान हादसे ने लोगों की ऐसी चिंता और बढ़ाई होगी। यह सही है कि विमानन कंपनियां रोजाना तमाम तरह की समस्याओं से दो-चार होती है, लेकिन हवाई यात्रा अभी भी आवाजाही का सबसे सुरक्षित माध्यम है। विमान हादसे के बाद इन दिनों छोटी-मोटी समस्याओं को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह सही नहीं। निधि राजदान@Nidhi

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भारत का ईरान, इजरायल में से किसी के साथ न खड़े होने का फैसला सही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग का सामना करने के पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जुगनू जैसा देश है पर हौसले बुलंद,
अपने दुश्मन मुल्क की करे बोलती बंद।
करे बोलती बंद नाम उसका इजरायल,
उसकी हिम्मत देख हो रही दुनिया कायल।
रेंगे जिसके कान न सीधी उंगली से जू,
घुसता उसके कान जाय यह छोटा जुगनू!
- ओमप्रकाश तिवारी

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

पंजाब डायरी

तीस साल के इतिहास को दोहराता उपचुनाव

लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के परिणाम पर टिकी नजर। प्रतीकात्मक

कभी-कभी एक छोटा-सा चुनाव भी राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देता है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब ऐसा होता है, तो प्रदेश में आने वाले चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंजाब के लुधियाना पश्चिमी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य और प्रसिद्ध उद्योगपति संजीव अरोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। सवाल है कि क्या यह उपचुनाव तीस साल पहले हुए उपचुनाव जैसा साबित होगा? यह सवाल इस समय प्रदेश के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस उपचुनाव और तीस साल पहले हुए उपचुनाव में कई समानताएं हैं।

पहली सबसे बड़ी समानता यह है कि साल 1992 और 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों सत्तारूढ़ पार्टियां क्रमशः कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित रूप से 92-92 सीटें जीतकर आई थीं। अंतर केवल इतना है कि 1992 में शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जबकि 2022 में मतदाताओं ने शिरोमणि अकाली दल को मात्र तीन सीटें देकर हाशिये पर धकेल दिया। दोनों ही उपचुनाव जून महीने में हो रहे हैं, जो पंजाब में सबसे गर्म महीना माना जाता है। 45 डिग्री से अधिक तापमान चुनावी गर्मी को और बढ़ा देता है। एक-एक वोट के लिए उम्मीदवारों को किस प्रकार पसीना बहाना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है।

वर्ष 1992 में सत्ता में आने के बाद पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के लिए 1995 का गिदड़बाहा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद अहम था। दरअसल प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सीट गिदड़बाहा को छोड़ अपने भतीजे के हवाले कर दिया था, जिसे वह पांच बार जीत चुके थे। शिरोमणि अकाली दल के चुनावी मैदान में होते हुए बेअंत सिंह को जीत दर्ज करके उस कलंक को मिटाना था, जिसमें कहा जा रहा था कि मात्र आठ प्रतिशत वोट लेकर बनी हुई सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बेअंत सिंह ने उस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। एक-एक गांव में एक-एक मंत्री और विधायक बिठा दिए। पैसा पानी की तरह बहाया गया। दूसरी ओर, लंबे समय से राजनीतिक हाशिये पर चल रहे प्रकाश सिंह बादल अपने भतीजे मनप्रीत बादल को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। आखिरकार लगभग तीन हजार मतों से मनप्रीत बादल जीतने में सफल रहे। यही जीत पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हुई। साल 1997 में प्रकाश सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत लेकर पंजाब में 17 साल बाद सत्ता में लौटे।

तीन दशक बाद अब यदि लुधियाना पश्चिमी के उपचुनाव को देखा जाए, तो यह भी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1995 वाला उपचुनाव था। यदि यह चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी जीत जाती है, तो राज्यसभा की एक सीट खाली हो जाएगी, जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल या कोई अन्य बड़ा नेता राज्यसभा जा सकता है। यदि सत्तारूढ़ पार्टी यह चुनाव हार जाती है, तो उसे अपनी सरकार को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही भारी बहुमत है, लेकिन दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह कठिन हो जाएगी। इस बात की संभावना भी प्रबल है कि जिस प्रकार से पार्टी अपनी छवि गंवा रही है, उससे पंजाब में उसे अपनी सरकार को आगे दोहराने में मुश्किल आएगी।

पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद शिक्षा की बेहतरी और ड्रग्स के खात्मे के लिए दो बड़ी मुहिम चलाकर मान सरकार ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। इसमें उसे आंशिक सफलता तो मिली है, लेकिन जो वादे पार्टी ने 2022 में लोगों से किए थे, उनमें से कोई पूरा न करने के चलते उसकी छवि धूमिल हुई है। छवि ठीक रखना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है और 19 जून को लोग अपना फैसला देंगे, वह आम आदमी पार्टी के लिए कहीं गिदड़बाहा जैसा साबित न हो जाए, यह बात पार्टी के बड़े नेताओं को कचोट रही है।

मंथन

शिशिर शुक्ला
विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय, शाहजहांपुर

मानवीय मूल्यों का विकास जरूरी

उच्च शिक्षा का लक्ष्य महज अध्ययन एवं करियर निर्माण ही नहीं, अपितु विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक, संवेदनशील मनुष्य एवं नैतिक रूप से पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बनाना भी है

यूजीसी ने दिया मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर। फाइल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी शुरुआत पर विचार कर रहा है। यूजीसी द्वारा मूल्य आधारित शिक्षा के रूप में एक नई पहल की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस नवीन एवं बहुआयामी अभियान के अंतर्गत अब स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ मानव मूल्यों एवं प्रोफेशनल नैतिकता के विषय का भी अध्ययन करेंगे। ऐसा करने के उपरांत विद्यार्थी स्वयं को सामान्य नागरिक से वैश्विक नागरिक (ग्लोबल सिटीजन) में रूपांतरित कर पाने में सक्षम एवं समर्थ हो सकेंगे। पारंपरिक उच्च शिक्षा के परिदृश्य पर यदि गंभीरतापूर्वक गौर किया जाए तो वह कहीं न कहीं मात्र सीमित पाठ्यक्रम को पढ़कर चुनिंदा प्रश्नपत्रों की परीक्षा देने एवं उत्तीर्ण होने के उपरांत संबंधित पाठ्यक्रम की डिग्री हासिल कर लेने भर तक ही सीमित है। इस आपाधापी में शायद हम यह भूल चुके हैं कि आज की युवा पीढ़ी नैतिकता एवं मानव मूल्यों से शनैः शनैः दूर होती जा रही है।

आज के विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में उच्च शिक्षा के माहौल में दाखिल होने के उपरांत महज गिने-चुने शब्द जैसे पाठ्यक्रम, नोट्स, कोचिंग, परीक्षा एवं डिग्री ही घूमते रहते हैं। नतीजा यह निकल रहा है कि मानव मूल्य एवं नैतिकता, जो कि व्यक्तित्व निर्माण के आधार स्तंभ हैं, विद्यार्थियों से छूटते जा रहे हैं। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा में इन विषयों का पाठ्यक्रम के रूप में समावेश निःसंदेह ही एक बेहतरीन निर्णय है। जब यह परिवर्तन क्रियान्वयन के धरातल पर सफलतापूर्वक उतरेगा, तो निश्चित ही देश की युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्तर में एक बड़ा एवं सकारात्मक बदलाव आएगा, जो उनके सोच एवं समझ को दूरदर्शी बनाने एवं व्यापक रूप देने में सक्षम होगा। यूजीसी द्वारा की जाने वाली इस नई शुरुआत के अंतर्गत स्नातक एवं परास्नातक दोनों ही स्तरों पर मानव मूल्य तथा नैतिकता नामक विषय दो क्रेडिट अंकों के पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। इनमें से एक क्रेडिट अंक थ्योरी का तथा एक क्रेडिट अंक प्रैक्टिकल का रहेगा। थ्योरी का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को 15 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, जबकि प्रायोगिक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उन्हें इन विषयों से जुड़ी गतिविधियों में 30 घंटे शामिल होना पड़ेगा। स्नातक एवं परास्नातक दोनों ही पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर में इन विषयों के पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा।

आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य में मानव मूल्य एवं नैतिकता के स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। इस पतन का एक संभावित कारण यह भी है कि आज सामाजिक जीवन पर कहीं न कहीं प्रौद्योगिकी का भूत हावी हो चुका है। निःसंदेह प्रौद्योगिकी आज के समय में जीवन की अनिवार्यता बन चुकी है, किंतु कहीं न कहीं इसी प्रौद्योगिकी की वजह से युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित भी होती जा रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों के पतन अथवा पूर्ण लोप हो जाने के रूप में परिलक्षित हो रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों को मानव मूल्य, कौशल, एकीकृत व्यक्तित्व, वैश्विक नागरिकता, मौलिक कर्तव्यों, प्रेम, करुणा, सत्य, धर्म, शांति, अहिंसा, सेवाभाव, मित्रता, राष्ट्र प्रेम एवं सामाजिक जुड़ाव की ओर अभिप्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को विभिन्न गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं सार्वभौमिकता की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। ये सारे वही गुण हैं जिनका आधुनिक युवा पीढ़ी द्वारा कहीं न कहीं परित्याग किया जा चुका है। नैतिकता एवं मानव मूल्यों का पाठ्यक्रम में समावेश निश्चित रूप से विद्यार्थियों के नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगा। इन विषयों को सीखने एवं इनसे भलीभांति परिचित होने के उपरांत विद्यार्थी शैक्षिक विकास के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास, सामाजिकता की बेहतर समझ के विकास, विश्व बंधुत्व एवं वैश्विक कल्याण की भावना के विकास तथा जिम्मेदारी की भावना के विकास को उद्दीपित करने में समर्थ हो सकेगा।

यूजीसी की नई पहल जब पूर्णरूपेण क्रियान्वयन में आ जाएगी, तो निश्चित ही शिक्षा एवं शिक्षार्थी दोनों का स्वरूप तथा पारस्परिक संबंध एक बड़ी सीमा तक परिवर्तित हो जाएगा। यह परिवर्तन विद्यार्थियों के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के चहुंमुखी विकास हेतु एक उन्नत आधारशिला तैयार करेगा। उच्च शिक्षा का लक्ष्य महज अध्ययन एवं करियर निर्माण ही नहीं है, अपितु विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक, संवेदनशील मनुष्य एवं नैतिक रूप से पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बनाने का कार्य भी उच्च शिक्षा द्वारा ही किया जाता है।

****

epaper.jansatta.com

कल्पमेधा

जब बोलना चाहिए तब चुप रहना घातक हो सकता है और जब चुप रहना चाहिए तब बोलना फिजूल है।
- कन्फ्यूशियस

पाक फिर बेनकाब

पाकिस्तान आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है। वह न सिर्फ पनाह देता है, बल्कि आतंकियों की फौज तैयार कर उनका वित्त पोषण भी करता है। वहां की सेना और खुफिया एजंसी आइएसआइ इन आतंकियों को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को सबूतों के साथ उजागर कर चुका है। इसके बावजूद वह आतंकवाद से अपने जुड़ाव को हमेशा नकारता रहा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सीमा पार से प्रायोजित था, घटना की जांच के बाद मिले सबूत इसकी गवाही देते हैं। अब वैश्विक निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के एक बयान से भी इसकी पुष्टि हो गई है। उसने दो टूक कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था। इससे पाकिस्तान आतंकियों की धन-बल से मदद करने के मामले में एक बार फिर बेनकाब हुआ है। यह पहली बार है जब राज्य प्रायोजित आतंकवाद की अवधारणा को एफएटीएफ ने वित्तपोषण स्रोत के रूप में स्वीकार किया है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का यह बयान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पिछले दिनों 'आपरेशन सिंदूर' चलाकर सीमा पार कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके उपरांत भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने कई देशों में जाकर पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ को उजागर किया। वैश्विक निगरानी संस्था ने भले ही अपने बयान में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि आतंकियों को कौन वित्तीय मदद मुहैया कराता है। एफएटीएफ विभिन्न देशों में जांच का दायरा बढ़ाएगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके किन देशों में आतंकी वित्तपोषण हो रहा है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जांच के बाद इस पर एक रपट भी जारी की जाएगी। अगर रपट तैयार करने में निष्पक्ष व पारदर्शी प्रणाली अपनाई गई तो पाकिस्तान की असलियत फिर जगजाहिर होगी। भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है।

भारत अब इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान का नाम फिर से एफएटीएफ की 'ग्रे' सूची में डाला जाए। इस सूची में शामिल होने वाले देशों में आतंकी वित्तपोषण और धनशोधन जैसे मामलों की निगरानी की जाती है। पाकिस्तान को कई बार इस सूची में शामिल किया गया है। मगर, सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थान पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों है? 'आपरेशन सिंदूर' के बाद इन दोनों वैश्विक संस्थाओं ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को बड़ी राशि कर्ज के रूप में मंजूर की है। अगर, वैश्विक संस्थाएं वास्तव में आतंकवाद के खात्मे को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें सबसे पहले आतंकियों की मदद करने वाले देशों को चिह्नित कर उनकी वित्तीय व अन्य सहायता रोकनी होगी। सिर्फ आतंकवाद की निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए सही मायने में धरातल पर काम करने की जरूरत है।

मनमानी के विरुद्ध

देश में बौद्धिक विमर्श की क्या कोई गुंजाइश है या नहीं? अगर है तो फिर अभिनेता कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' का विरोध क्या सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जो लोगों को पसंद नहीं? मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि विरोध के बजाय इसे बौद्धिक बहस के तौर पर लिया जाना चाहिए था। सेंसर बोर्ड से प्रमाणित होने के बाद भी इस फिल्म के प्रदर्शन को जिस तरह रोका गया, उससे समझा जा सकता है कि विमर्श की कितनी जगह बची है। सहमति और असहमति के बीच संवाद भी एक रास्ता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभिनेता ने कुछ असुविधाजनक कहा, तो वह अंतिम सत्य तो नहीं था। लोगों को अलग-अलग विचार रखने का अधिकार है। मगर इस वजह से फिल्म का प्रदर्शन रोका नहीं जा सकता।

प्रमाणपत्र मिलने के बाद भी राज्य सरकार के मौखिक निर्देश और पुलिस की मदद से जिस तरह फिल्म के प्रदर्शन को रोका गया, उससे कई सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तान सकते। फिल्मों और विचारों के माध्यम से अभिनेता कमल हासन अपनी बात मुखर होकर रखते रहे हैं। इस बार वे विवादों में तब घिरे जब उन्होंने अपनी फिल्म 'ठग लाइफ' का आडियो जारी करने के समय कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी की। इसका राज्य में तीखा विरोध हुआ। कर्नाटक फिल्म चैंबर आफ कामर्स ने यहां तक कह दिया कि जब तक कमल हासन माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनकी फिल्म राज्य में प्रदर्शित नहीं होने दी जाएगी। हालांकि, पांच जून को फिल्म देशभर में प्रदर्शित हो गई, लेकिन कर्नाटक में इसे रोक दिया गया। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार से इसकी न केवल वजह पूछी, बल्कि यह भी कहा कि फिल्म देखने से रोकने के लिए नैतिकता के कथित पहरेदारों को सड़कों पर कब्जा व हंगामा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निस्संदेह विरोध के डर से राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से मुकर नहीं सकती।

अंतरिक्ष के रहस्य और जीवन की खोज

सुदूर अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को लेकर एक नई खोज ने विज्ञान जगत को उम्मीदों की नई रोशनी दी है। इस खोज से उस जटिल और अनसुलझे सवाल को हल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जवाब मानव वर्षों से तलाश रहा है।

ऋतुपर्ण दवे

सृष्टि के निर्माण के समय से ही अंतरिक्ष रहस्यों का विषय बना हुआ है। मानव ने भले ही चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों तक पहुंच बना ली है, लेकिन अंतरिक्ष में पल-पल घट रही अद्भुत और विस्मयकारी घटनाओं एवं पृथ्वी से इतर जीवन की संभावनाओं तथा गहराइयों को जानने-समझने में अभी वक्त लगेगा। उड़न तश्तरी और एलियन को लेकर कई तरह के किस्से सुनने को मिल जाते हैं। कोई दो मत नहीं कि अंतरिक्ष का रहस्य, रोमांच से भरपूर है। उसमें भी अहम यह कि क्या धरती के अलावा, दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? इसको लेकर एक नई खोज ने अंतरिक्ष विज्ञान जगत को उम्मीदों की नई रोशनी दी है।

दरअसल, साठ के दशक में अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र के रेडियो एंटिना रिसीवर ने पक्षियों की चहचहाहट सुनीं, जिन्हें 'कोरस वेव्स' कहते हैं। नासा के जुड़वां अंतरिक्ष यान वैन 'एलन प्रोब्स' के रेडिएशन बेल्ट में भी ये आवाजें सुनी गई थी। बाद में वर्ष 2015 में नासा के ही एक उपग्रह ने भी ऐसी तरंगों को रेकार्ड किया। ऐसी रहस्यमयी आवाजें, रेडियो सिग्नल, तैरते हुए पानी का विशाल भंडार दिखना, अंतरिक्ष यात्रियों का एक दिन में कई बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखना सचमुच रोमांचकारी है। वैज्ञानिक इन रहस्यों को समझ पाते, इसी बीच कैंब्रिज विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली खोज और तथ्यों से चकित कर दिया। उनकी इस खोज पर पूरी दुनिया में चर्चा है। उनका दल ऐसे रहस्यों को खोल रहा है, जो सदियों पुराने हैं।

इस धरती से बहुत दूर एक बाह्य ग्रह मिला है, जिसे के2-18बी नाम दिया गया है। यह वरुण से छोटा है। एक लाल तारा भी मिला, जो सूर्य से आकार और द्रव्यमान में बहुत छोटा, ठंडा, और नारंगी रंग का है। ऐसे तारे सबसे आम और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले होते हैं। कैंब्रिज के खगोलशास्त्री मधुसूदन और उनके दल के पास ऐसे पुख्ता आधार हैं, जिनमें वहां ऐसे अणुओं के संकेत मिले जिनका अब तक केवल पृथ्वी पर ही मिलना संभव समझा जाता था। सबसे बड़ी विशेषता यह कि ये केवल साधारण सूक्ष्म जीवों से ही पैदा होते हैं। के2-18बी आकार में पृथ्वी से ढाई गुना बड़ा और 700 ट्रिलियन मील दूर है। यह भी ऐसा बाह्य ग्रह है जो अन्य पिंडों की तरह परिक्रमा करता है।

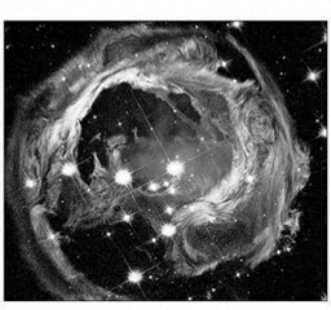

अध्ययन के दौरान पाया गया कि सुदूर अंतरिक्ष के उस वातावरण के दो अणुओं में से एक में रासायनिक छाप हैं, जो ऐसे अर्ध-रसायनों की विशेषताओं को दर्शाते हैं। इनमें उसके मूल या सर्वव्यापी यौगिक भी शामिल होते हैं। इनके निर्माण की विशेषता यह है कि ये पौधों और प्लवक यानी कीटों के बीच की अंतःक्रिया से ही बनते हैं। स्वाभाविक है वहां जीवन के बिना ऐसा हो पाना संभव ही नहीं होगा। इसलिए इस शोध या खोज को लेकर दुनिया

उत्साहित है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस बाह्य ग्रह की खोज से और चौंकाने वाले तथ्यों का पता लगने की संभावना है। खोजकर्ताओं को यहां डाईमिथाइल सल्फाइ (डीएमएस) नाम की गैस मिली। यही गैस

> **कैंब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के वैज्ञानिक मधुसूदन एक जटिल और अनसुलझे सवाल को हल करने में जुटे हैं। उनकी खोज से ऐसे ग्रहों के भी रहस्य खुलने का इंतजार है, जहां महासागर जैसा वातावरण और हाइड्रोजन से भरपूर वायुमंडल हो। इस खोज ने अब तक के सारे कयासों और मिथकों से अलग वास्तविकता तथा वैज्ञानिक आधारों को बल दिया है। धरती से बहुत दूर और धरती पर रह कर सुदूर ग्रह पर ऐसे संकेत खोजना वास्तव में रोमांच से भरा है। खगोलशास्त्री मधुसूदन की इस खोज की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है।**

धरती पर केवल जैविक प्रक्रिया से बनती है। इससे लगता है कि उस ग्रह पर जीवन के होने की संभावनाएं प्रबल हैं। यह रसायन एक कार्बनिक यौगिक है, जो ज्वलनशील, रंगहीन और तरल होने के साथ गंध से युक्त होता है। यह कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक उपयोगी रसायन है, जैसे पेट्रोलियम शोधन और एथिलीन उत्पादन। कुछ शोधों में इसे एलियन रूपी जीवन के संकेत के रूप में भी देखा गया है। इसके पुष्ट कारण भी हैं, क्योंकि यह पृथ्वी पर केवल जीवित जीवों द्वारा निर्मित होता है। इस खोज से ऐसे ग्रहों के भी रहस्य खुलने का इंतजार है, जहां महासागर जैसा जलमग्न वातावरण और हाइड्रोजन से लबरेज भरपूर वायुमंडल हो। ग्रह के वायुमंडल, संरचना और उसमें जीवन की संभावनाओं पर केंद्रित खगोलशास्त्री मधसूदन की खोज ने अब तक के सारे कयासों और मिथकों से अलग वास्तविकता तथा वैज्ञानिक आधारों को बल दिया है। उन्होंने ही 'हाईसीन वर्ल्ड' शब्द सुझाया, जिसका तात्पर्य यह कि ऐसे ग्रहों पर हाइड्रोजन युक्त वातावरण और तरल पानी के महासागर होते हैं।

दूसरे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऐसे ग्रहों पर सूक्ष्म जीवों के लिए जी पाना संभव है। इस खोज के निष्कर्ष तक पहुंचने में दो-तीन वर्ष और लग सकते हैं और दुनिया को इसका बेसब्री से इंतजार है। कैंब्रिज विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भारतीय मूल के वैज्ञानिक मधुसूदन उस जटिल और अनसुलझे सवाल को हल करने में जुटे हैं, जिसका जवाब मानव सदियों से खोज रहा है। यह सवाल हमेशा उठता रहा है कि क्या एलियन वाकई में हैं? लगता है यह खोज इस जटिल और अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठा सकती है। मधुसूदन की इस खोज की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इससे पता चलता है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें तराशने व प्रतिभा पलायन को रोकने की।

अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को लेकर पहले भी खोज व दावे किए जाते रहे हैं। वर्ष 2015 में नासा ने ग्राउंड वाटर आब्जरवेट्रीज की मदद से अनुमान लगाया था कि मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र में पृथ्वी के आर्कटिक महासागर से भी ज्यादा पानी था। करीब 300 करोड़ साल पहले यह समुद्र गायब हो गया, इसका करीब 87 फीसद पानी गुम हो गया, संभव है कि यह पानी खनिजों में मिल गया हो, या अंतरिक्ष में उड़ गया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां पानी होता है, वहां जीवन की पर्याप्त संभावना होती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए पिछले साल एक और बाह्य ग्रह की खोज की थी। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम एलएचएस 1140 बी रखा है। इस पर भी पानी होने और जीवन के लिए पृथ्वी जैसे स्थितियां होने के संकेत मिले हैं। इसी तरह हवाई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की ऊपरी ठोस सतह के नीचे मिथेन गैस दबी है। अब तक अध्ययन में पृथ्वी के बाद यह एकमात्र ऐसी जगह मानी जा रही है, जहां वातावरण मौजूद है और तरल पदार्थ नदियों, झीलों और समुद्रों के रूप में मौजूद है। अध्ययन में संभावना जताई गई है कि टाइटन पर किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद हो सकता है।

विचारों में गुम चेतना

दुनिया मेरे आगे

मोहम्मद जुबैर

हम कितनी बार किसी जगह पर होते हुए भी वहां मौजूद नहीं होते हैं? कई बार हम दफ्तर से घर तो आ जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं। परिवार में होते हुए भी उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसा भी होता कि कोई किताब पढ़ते हैं, शब्द आंखों के सामने से गुजरते जाते हैं और हम मर्म को समझे बिना पन्ने पलटते रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि भोजन तो खत्म हो जाता है, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि उसका स्वाद कैसा था। ऐसा भी होता है कि हम किसी से बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन सच में सुन नहीं रहे होते हैं। खुशियों के पलों में भी हम पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाते हैं। किसी हंसी-मजाक में हिस्सेदार होकर भी खुश नहीं होते हैं। इसी तरह रात को सोने के लिए बिस्तर पर तो चले जाते हैं और आंखें मूंद लेने के बावजूद सो नहीं पाते हैं। ये सब सामान्य स्थितियां तो नहीं हैं, लेकिन आखिर हम कहां गुम रहते हैं? यह एक ऐसा सवाल है, जिससे कभी न कभी और कोई न कोई जरूर सामना करता है।

अगर हम गौर करें तो इन स्थितियों के पीछे बड़ी वजह मन का भटकाव और वर्तमान से हमारा टूटता जुड़ाव है, जो अनावश्यक और अत्याधिक सोचने से होता है। हमारा दिमाग अक्सर दो दुनिया के बीच झूलता रहता है- एक वह, जहां हम सच में हैं और दूसरी वह, जहां हमारी चिंताएं हमें खींच ले जाती हैं। बीती हुई घटनाएं और आने वाले कल की चिंता, सब मिल कर हमारे वर्तमान को छीन लेती हैं। मनोवैज्ञानिक चिंता में घुलने या सोचने की तुलना दलदल से करते हैं, जो हमें अनिश्चितता और भय की ओर ले जाती है। हम अपने मन के भीतर गूंज रही धारणाओं और कल्पनाओं में ही उलझे रहते हैं। भीड़ भरा मस्तिष्क शांत चित के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। हम प्रायः अपने भीतर ही गुम रहते हैं।

> **असल में हम अपनी सोच की निर्मित दुनिया में जीते हैं। हम सिर्फ वही महसूस करते हैं, जो सोच रहे होते हैं। सोच-विचार वास्तविकता नहीं है, लेकिन इन्हीं के जरिए हमारी वास्तविकताएं निर्मित होती हैं। अगर हम किसी स्थिति को सकारात्मक रूप से देखें, तो वह आशा और प्रेरणा दे सकती है।**

ज्यादातर लोग अनावश्यक सोचने की अवस्था में दिन का अधिकांश हिस्सा बिताते हैं। अनावश्यक किसी विषय पर सोचते रहना हमारा समय ही व्यर्थ करता है। जोसेफ नूयेन अपनी पुस्तक 'डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक' में जोर देकर कहते हैं कि हमारा सोचते रहना हमारी चिंता की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल, हम चिंताओं में उलझकर शांति, प्रेम, संतुष्टि और आनंद जैसे कीमती रत्नों को धूमिल कर देते हैं, जबकि ये रत्न हमें स्वाभाविक रूप से मिले हैं। हम चिंता में डूबे रहते हैं, जो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, बल्कि बढ़ाती है। इस सच्चाई की पुष्टि कबीर के दोहे से की जा सकती है- 'चिंता वाकी कीजिए, जो अनहोनी होय/अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होय।' यानी, जो कभी होना ही नहीं, उसकी चिंता कैसी? और जो होना ही है, वह तो होकर ही रहेगा। यही जीवन का सत्य है। जिस पल हम सोचना कम करते हैं, उसी पल हमारी खुशी शुरू हो जाती है। असल में हम अपनी सोच की निर्मित दुनिया में जीते हैं, जहां हर भावना, हर अनुभव हमारे सोचने का प्रतिबिंब होते हैं। हम सिर्फ वही महसूस करते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं। सोच-विचार वास्तविकता नहीं है, लेकिन इन्हीं के जरिए हमारी वास्तविकताएं निर्मित होती हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल दें, तो वास्तविकता भी बदल जाती है। अगर हम किसी स्थिति को सकारात्मक रूप से देखें, तो वह हमें आशा और प्रेरणा दे सकती है। लेकिन वही स्थिति अगर नकारात्मक सोच के साथ देखी जाए, तो निराशा और भय उत्पन्न करती है।

ये दुनिया एकदम शीशमहल की तरह है, जहां लाखों शीशे जड़े हैं। अगर हम खुश रहते हैं, तो शीशे में बनने वाली हरेक छवि मुस्कुराती दिखती है और सकारात्मक ऊर्जा देती है। इसके विपरीत, अगर हम उदास या चिंतित होते हैं, तो शीशे में बनने वाली प्रत्येक छवि मायूस करने वाली होती है और नकारात्मकता भी हमें चारों ओर से घेर लेती है। यह संदर्भ जीवन के उस सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम प्रतिध्वनि का नियम कह सकते हैं- हमारी सोच, भावनाएं और कर्म हमें उसी रूप में लौट कर मिलते हैं।

हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन और परिवेश भी सकारात्मक और आनंदमय बन सके। वर्तमान वह एकमात्र समय है, जहां हम वास्तविकता को देख सकते हैं। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने कहा है 'जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो।' हम वास्तविकता के नहीं, सोच-विचार के संसार में उलझे रहते हैं, जो चिंता, तनाव, कुंठा, क्रोध और आत्मशंका को बढ़ाती हैं। जीवन में दुख-दर्द और समस्याएं आती रहती हैं, जो स्वाभाविक हैं। इनसे बचना संभव नहीं है, लेकिन इनसे मिलने वाले कष्ट से बचा जा सकता है, क्योंकि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जब हम किसी दुखद परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, धैर्य और समझदारी से उसका सामना करते हैं, तो हम कष्ट को न्यूनतम कर सकते हैं। कायदे से देखें तो यह बहुत आसान तरीका है, क्योंकि सच सरल ही होता है।

चौपाल

भारत की भूमिका

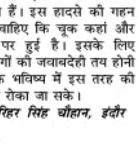

ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में भारत की भूमिका अहम हो गई है। प्रधानमंत्री का मूल मंत्र 'यह समय न युद्ध का है और न ही आतंकवाद का', दुनिया के लिए एक सीख की तरह है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 'आपरेशन सिंदूर' की सफलता के बावजूद इसे युद्ध में तब्दील नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था कि युद्ध होने पर भारत, पाकिस्तान से पिछड़ जाता। मात्र 29 मिनट के हवाई हमले में ही पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था। भारत चाहता तो इस बार आसानी से और भी बड़े कदम उठा लेता। मगर, भारत ने अपने मूल मंत्र को ध्यान में रख कर ही संघर्षविराम के लिए हामी भरी। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। रूस-यूक्रेन युद्ध लंबे समय से जारी है। ईरान पर हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक दिन में 13 फीसद बढ़ गई। यह वही इलाका है, जिसकी हिस्सेदारी वैश्विक तेल उत्पादन में एक तिहाई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर मंथन होना चाहिए।

- युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

समय की सीख

अहमदाबाद विमान हादसे से सभी देशवासी दुखी हैं। यह घटना बड़ा सबक भी है। आधुनिकता के इस युग में विश्व ने कितनी ही उन्नति कर ली हो, पर समय चक्र के आगे सभी नतमस्तक है। मौत किस प्रकार चंद सेकंड में आती है और अपने साथ ले जाती है, यह सभी ने देखा। कभी किसी ने इस प्रकार की घटना के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत में सुरक्षित विमान सेवाएं अपना अलग मुकाम रखती हैं। इस पर हमेशा भरोसा रहा। मगर न जाने किन कारणों से इतना बड़ा हादसा उस दिन हो गया। अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। इस हादसे की गहन जांच होनी चाहिए कि चूक कहां और किस स्तर पर हुई है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

- हरिहर सिंह चौहान, इंदौर

लापरवाही की हद

ऐसा लगता है कि जैसे यह हादसों का देश है। यहां हर रोज कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं, चाहे वह प्रशासन की लापरवाही हो या आम जनता की। कभी भगदड़ मच जाती है, कभी नदियों में नावें डूब जाती हैं, तो कभी सड़क हादसे होते हैं। नदियों पर बने हुए पुल ढह जाते हैं। अभी हाल ही में अहमदाबाद में विमान दुर्घटना से लोग उबरे भी नहीं थे कि केदारनाथ में हेलिकाप्टर गिरने की खबर आ गई। फिर पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। इन सभी हादसों में कई जिंदगियां खत्म हो गईं। हर वर्ष सैकड़ों लोग हादसों में अपनी जान गंवा बैठते हैं। हर हादसे के बाद प्रशासन जांच समिति बना देता है। समय बीत जाता है और कई मामलों में जांच समिति की रपट भी औपचारिकता बन जाती है। इन हादसों को वे ही लोग याद रखते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया होता है।

- चरनजीत, नरेला, दिल्ली

नियमों का पालन जरूरी

कोरोना के आंकड़े फिर डरा रहे हैं। चिकित्सक भले ही कह रहे हैं कि यह पिछली बार की तुलना में कम घातक है, लेकिन यह कब घातक रूप धारण कर ले, कहा नहीं जा सकता। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन ईमानदारी से करना होगा। हम केवल सरकार के भरोसे बैठ कर कोरोना से नहीं लड़ सकते। इसलिए अभी से जागरूक होकर नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा होने से बचना होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी कोरोना ने किस कदर कहर बरपाया था। इसी कोरोना ने रिश्तों की पहचान कराई थी। तब रिश्ते-नातेदारों ने कोरोना मरीज से ऐसी दूरी बना ली थी, जैसे वह उनका कोई नहीं? लोगों का पैसा बैंकों और घरों में पड़ा रह गया था।

- अरविंद रावल, गोपाल कालोनी, झाबुआ

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

epaper.jansatta.com